an>

title: Shri Anurag Singh Thakur called the attention of the Minister of Defence regarding the recent disclosure by the Court of Appeals, Milan, Italy on alleged irregularities in Agusta Westland Helicopter deal, 2013.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"Recent disclosure by the Court of Appeals, Milan, Italy on alleged irregularities in Agusta Westland Helicopter deal, 2013."

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर): अध्यक्ष महोदया, मैंने स्टेटमेंट सभा पटल पर रख दिया है लेकिन उसके प्रमुख बिन्दु की ओर सभागृह का ध्यान आकर्Âिषत करना चाहता हूं। अगस्टा वेस्ट लैंड के पूरे मामले को प्रायः दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक, ऑर्डर देने के समय तक जो कुछ हुआ और दूसरा, ऑर्डर देने के बाद जब वर्ष 2012 में न्यूज पेपर में भ्रÂष्टाचार के मामले सामने आने लगे, उसके बारे में है। दूसरा भाग जो है, उसमें जब गवर्नमेंट वर्ष 2014 में बदली, उसके बाद जो अभी तक का मामला हुआ है, उसके बारे में है।

मैं इसमें पहले बोलना चाहता हूं कि जब वर्ष 1999 में अटल जी की सरकार थी, उस समय यह वीआईपी प्रोक्योरमेंट का प्रोसिजर चालू हुआ। एमआई -8 हेलिकॉप्टर थोड़े पुराने हो गये थे और वर्ष 2002 में इसके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब टेंडर इश्यू किया गया था। लेकिन, उससे जो निकला, 11 वेंडर्स को टेंडर दिए गए थे, लेकिन केवल चार सामने आ गये, उनमें से तीनों ने जो कोट दिया था, उसका विश्लेÂषण किया गया, केवल दो वेंडर्स फाइनल स्टेज तक आये। जब उसका फील्ड इवैलुएशन ट्रायल हो गई तो केवल ईसी-225 हेलिकॉप्टर्स पास हुए। सिंगल वेंडर होने के कारण, उस समय के सरकार ने इसको रद्द कर दिया। वर्ष 2003, दिसम्बर में, उस समय के पीएमओ ने डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरफोर्स को लिखा कि इसमें आपने जो एसक्यूआर, जो रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं, वे काफी टाइट हैं, इसके लिए आपने रिक्वायरमेंट के लिए 6000 मीटर की जो सिलिंग लगाई है, उसको कम करके 4500 मीटर तक कर दीजिए तो ब्रॉड बेस्ड हो जायेगा, वेंडर्स ज्यादा आ जायेंगे। उन्होंने उसके साथ यह भी सूचित किया था और मैं यहां यह बिंदू सभी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसके साथ 6000 मीटर तक की सिलिंग, will be a preferential, desirable character लेकिन कम्पलसरी कैरेक्टर में मत लाओ। उसके साथ एक और सजैशन दिया था कि कैबिन हाइट डिजायरैबल कैरेक्टर में 1.8 मीटर तक बना दें। इसमें कई जगह थोड़ा कंफ्यूज़न करने की कोशिश है कि 1.8 मीटर और 4500 मीटर से जो कम कर दिया, इसके लिए सब आगे का हो गया, इसके लिए आगे नहीं हुआ। वर्ष 2005 में एक निर्णय लिया गया, उसमें उसकी सिलिंग हाइट 6000 मीटर से कम करके 4500 मीटर तक कम कर दिया गया। जिसके कारण, the vendor base is expanded. लेकिन उसके साथ एक नया एसक्यूआर, एशेंसियल एसक्यूआर डाल दिया गया कि इससे केबिन हाइट 1.8 मीटर और यह बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, 1.8 मीटर केबिन हाइट उसमें कम्पलसरी एसक्यूआर रिक्वायरमेंट करके डाला गया। जब 1.8 मीटर कम्पलसरी एसक्यूआर डाला गया तो ऑटोमैटिकली उससे पहले से जो सेलेक्ट हुआ था, एफईटी में जो हेलिकॉप्टर ईसी-225 पास हुआ था, यह ऑटोमैटिक रेस में से बाहर निकल गया। It was virtually thrown out of the race by specific requirement of 1.8 metre which was introduced on 9th May, 2005 by UPA-I Government. अगस्टा वेस्ट लैंड का एडब्ल्यू 101 को हाइट सिलिंग के कारण अंदर प्रवेश दिया गया।

अटल जी के समय दो वैंडर बेस बड़े बनाने के लिए हाइट सीलिंग कम करने को कहा था। उससे वैंडर बेस बड़े बन गए, लेकिन 1.8 कैबिन हाइट डालने के कारण वैंडर बेस और भी सिंकुड़ हो गए। इसका फाइनली एओएन (ऐक्सैप्टैंस ऑफ नैसेसिटी) 3 जनवरी, 2006 में दिया गया जिसमें केवल 6 वैंडर को आरएफपी या टैंडर डॉक्यूमैंट दिए गए। पहली बार 11 वैंडर थे, अभी 6 वैंडर पर नीचे आ गए क्योंकि एसक्यूआर 2005 में और रिस्ट्रिक्टिव बनाया गया। जब एओएन दिया था, उस समय इस हेलिकॉप्टर परवेज़ की कीमत 793 करोड़ रुपये बताई गई थी।

मैं इसमें एक चीज पूरे सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 793 करोड़ रुपये कैसे कैलकुलेट किए गए। इसमें प्राय: तीन हेलिकॉप्टर्स लिए गए थे जिसका प्राइस लिया गया था। एक एमआई-17 ब्लॉक 5 रशियन हेलिकॉप्टर जिसकी कीमत तकरीबन 35 करोड़ रुपये ऐस्टीमेट की गई थी। दूसरा, एस-92 सिकोरस्की का, जिसकी कीमत तकरीबन 60 करोड़ रुपये दी गई थी और तीसरा, एडब्ल्यू-101 अगस्टा वैस्टलैंड का जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये दिखाई गई थी, उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से तकरीबन 15 मिलियन यूरो रोजर थे। इसकी मीड़ वैल्यू निकालकर एओएन में पूरे परवेज़ की कीमत 793 करोड़ रुपये दिखाई थी। एओएन में एसओसी यानी स्टेटमैंट ऑफ केस में अगस्टा वैस्टलैंट का प्राइस 100 करोड़ रुपये दिखाया गया है जिसका मतलब 15 मिलियन यूरोज़ हैं। यह सिलसिला पूरी बात में चलता रहा। कई कनसेशन दिए गए और वे सब कनसेशन अगस्टा वैस्टलैंड को दिए गए। थोड़े एस-92 को भी दिए गए। उसमें से पहला फील्ड इवैलुएशन ट्रायल जो टैंडर्ड इक्विपमैंट या आरएफपी में लिखा था कि यह ट्रायल आपको भारत में करना है और उसका कारण है। इस देश की वैदर कंडिशन, एवसट्रीम टैम्परेचर, सभी टैम्परेचर में जहां यह यूज़ होने वाला है, वहां सभी जगह इसका ट्रायल लेना है। जब आरएफपी में लिखा था कि भारत में होना है, उस समय दोनों वैंडर ने कहा कि यह हम अपने देश में करेंगे। उस समय के रक्षा मंत्री ने काफी रैज़िस्टैंस किया था। उन्होंने लिखा था कि यह बराबर नहीं है। लेकिन बाद में न जाने क्यों उन्हें कनविंस किया गया। पेपर, फाइल में सब लोगों ने लिखा यह करना जरूरी है। उन्होंने बाद में इसे यूके में करने के लिए सहमति दे दी। इस प्रकार एफईटी टैंडर्ड डॉक्यूमैंट में लिखे हुए क्लॉज़ के खिलाफ देश के बाहर हुआ। कई लोग कहते हैं कि आरएफपी में अभी भी जो 16 में आया है, उसमें बाहर करने से बंधन नहीं है, there is no ban; I agree with it. लेकिन टैंडर्ड डॉक्यूमैंट में लिखा था कि इस देश में करना है।

एक और अजीब चीज हो गई थी कि टैंडर्ड डॉक्यूमैंट जो छ: वैंडर को दिए गए थे, वह अगस्ता वैस्टलैंड, इटली को दिया गया था। लेकिन जो टैंडर भरा, वह अगस्ता वैस्टलैंड इंटरनैशनल लिमिटेड (एडब्ल्यूआईएल), यूके कम्पनी ने भरा। इसके कई लीगल इमप्लीकेशन हैं। उसके बाद भी इसके लीगल इमप्लीकेशन सामने आए हैं जिसमें एक में इस कम्पनी ने अपने जवाब में कहा है कि हमारा और उनका क्या, वे अगर करप्शन में हैं तो हमें क्यों उसमें खींच रहे हैं। वे बाद में जब जवाब दे रहे थे, उस समय उन्होंने कोट किया है। They are going to use this in a legal battle whenever it takes place. लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी मैंने कभी नहीं देखा कि टैंडर्ड डॉक्यूमैंट एक कम्पनी को दिया हो और टैंडर कोट करने वाली कम्पनी अलग हो। ...(व्यवधान) यह स्पÂष्ट चीज से सामने आया है। मैं बोलना चाहता हूं कि एडब्ल्यूआईएल उनके ओन एडमिशन के हिसाब से यह कम्पनी केवल कस्टमर रिलेशन और कस्टमर को डिज़ाइन करने वाली कम्पनी है। यह कम्पनी ओईएम नहीं है, ओरिजनल इक्विपमैंट मैनुफैक्चरर नहीं है, उनके पास ओईएम की फैसिलिटी नहीं है। उन्होंने बाद में ये सब कौन्ट्रैक्ट अगस्ता वैस्टलैंड को ट्रांसफर कर दिए। इसके पूरे डॉक्यूमैंट हमें इटली कोर्ट से, जब हम सिविल पार्टी बन गए थे, उसमें पूरे डॉक्यूमैंट मिले।

फेयर ट्रायल के बाद ध्यान में आया कि 12 में से 4 नॉन वीआईपी हेलीकॉप्टर और 8 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर थे, इसमें दो कंडीशन हेलीकॉप्टर कंपनी मीट नहीं कर रही थी यानि दो कंडीशन पूरे नहीं हो रहे थे। सिरकोस्की एस-92 में चार कंडीशन मीट नहीं हो रहे थे, डीपीपी का 75 पैरा के तहत कन्सेसन दे सकते हैं, आठ-दस कलाऊजेज को रिलेक्सेसन दिया गया जिसका इम्पैक्ट सैलेक्शन पर हुआ। इसमें केवल अगस्ता वेस्टैंड को कन्सेसन दिया गया, दो कंडीशन मीट नहीं हो रहे थे उसमें उनको रिहाई दी गई। लेकिन एस 92 को रिहाई नहीं दी गई, एक्चुअली यह बहुत ही इम्पोर्टैंट क्लाउज है क्योंकि 1975 से कन्सेसन देते हैं लेकिन यह रेअरली यूज़ होने वाला क्लाऊज है extraordinary powers to be used in a rare condition. You cannot give it in a resultant single vendor case. उसको कन्शेसन देकर सिंगल वेंडर को ही फाइनलाइज कर दिया गया, अगर एस 92 को भी 4 कन्शेसन दे देते तो मैं समझ सकता था लेकिन एक ही कंपनी को कन्सेसन दिया और उसे सिंगल वेंडर बना दिया। बाद में सीएनसी हो गया और प्राइस का बेंचमार्किंग हो गया। उसमें आपने जो प्राइस दिखाया वह प्राइस छह गुना ज्यादा था जो एओएन में प्राइस दिखाया था। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोल रहा है कि ओपन सोर्सेज 2010 में बेस हेलीकॉप्टर एडब्ल्यू 100 का 18 मिलियन 2010 में दिखा रहे हैं। यह कोर 2008 में था। एओएन में बेस प्राइस एयरफोर्स ने 15 मिलियन दिखाया था उस समय सीएनसी बेंचमार्किंग करने वाली टीम थी उन्होंने उसका बेस प्राइस 27 मिलियन पकड़ा था। जब आप सिंगल वेंडर सिच्युएशन में कन्सेसन देने के बाद यह सब चीज करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि price is a very important factor. क्योंकि सिंगल वेंडर को कम्पेयर करने के लिए दूसरे को नहीं होना चाहिए था इन लोगों ने एओएन में 100 करोड़ प्राइस दिखाया था यानि 15 मिलियन यूरो दिखाया था उसे दो वर्ष के गैप में 27 मिलियन क्यों लिया इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इन्होंने 27 मिलियन बेस्ड लिया और फाइनली इसे बढ़ाकर 4877.50 करोड़ रुपये का बेंचमार्किंग कर दिया यह एस्टिमेटेड प्राइस है, यह डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में प्रोसिजर है। इस प्रोसिजर में थोड़ी-बहुत रिलेक्सेसन मिलेगा अगर आप मल्टी वेंडर हैं लेकिन एक वेंडर होगा तो benchmarking is a criteria. जो एस्टिमेटेड टेंडर था उससे बेंचमार्किंग आगे कर दी गई थी, एओएन के हिसाब से कई गुना कर दी। दो गुना-ढाई गुना समझा जा सकता है लेकिन छह गुना कर दिया। मैं अभी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूं, एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स हैं मुझे बता रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर को जिस कन्डीशन में

हम लेना चाह रहे थे उस समय के प्राइस के हिसाब से 25-26 मिलियन यूरो ठीक प्राइस होता। बेंचमार्किंग इतनी हाई क्यों कर दी? उसका कारण बहुत सीधा है। जब टेंडर का इन्वेलेप खोला उस समय प्राइस 592 मिलियन यूरो निकला। अभी अप्रूव करने में इजी हो गया क्योंकि बेंचमार्किंग उससे ज्यादा था। फाइनली सब कुछ करते -करते 556.26 मिलियन यूरो पर प्राइस तय हो गया और आर्डर दे दिया गया। यह उसका पहला चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में पेमेंट का कंडीशन था, 8 फरवरी, 2010 को 15औ एडवांस पेमेंट डिलीवर हो गया। मार्च, 2011 में 30 औ पेमेंट दिया गया था। पहले का पेमेंट था 84.44 मिलियन यूरो और 166 और दोनों का 250.32 मिलियन यूरो पेमेंट कंपनी को चला गया था। Without that they asked the Embassy to find that out. लेकिन वर्ष 2012 की फरवरी में, जो दूसरा चैप्टर है, वह बहुत महत्व का है। पहले चैप्टर में कंपनी को फेवर करने के लिए अलग-अलग क्लॉजेज कैसे चेंज कर दिए गए, इसका ब्यौरा मैंने अपने रिटन स्टेटमेंट में दे दिया है, लेकिन मैं अब क्लीयरली इसलिए बता रहा हूं, ताकि लोगों के ध्यान में आए कि हरेक जगह, जब इस कंपनी को कॉंट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, तो उस समय क्लॉजेज रिलैक्स की गई।

महोदया, दूसरा ब्यौरा फरवरी, 2012 से शुरू हुआ। पहले न्यूज़ पेपर में आ गया कि इसमें भ्रÂटाचार हुआ है और नवम्बर, 2011 में इसके ऊपर इटली में केस रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन शुरू में किसी के ध्यान में यह बात नहीं आई। फरवरी, 2012 में मामला तब सामने आया, जब सरकार ने एम्बैसी को थ्रू एम.ई.ए. लिखा। अब आप देखिए कि आपने कॉंट्रैक्ट कंपनी के साथ किया है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंपनी को कुछ नहीं लिखा। कंपनी को लिखने की बजाय they asked Embassy to find out.

कभी-कभी जोक में हम लोग बोलते हैं कि जब आपको कुछ करना नहीं होता है, तो आप उस समय कमेटी बना देते हैं। ...(व्यवधान)... सुनिए, सुनिए।

स्पीकर मैडम, जो मैं बोल रहा हूं, उसके पूरे डॉक्युमेंट्स मेरे पास अभी यहां हैं। एम्बैसी को लिख दिया, एम्बैसी की ओर से गवर्नमेंट को लिख दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि यह इन्वेस्टीगेशन है। इसलिए आप इन्वेस्टीगेशन के पास जाइए। जब इन्वेस्टीगेशन वालों के पास गए, तो उन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी चालू है, सीक्रेसी है। इसलिए क्या इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते हैं। यह सब चल रहा था, लेकिन कंपनी को किसी ने नहीं लिखा। ...(व्यवधान)... वह तीसरे पार्ट में बताऊंगा। ...(व्यवधान)... मगर कुछ नहीं किया। ...(व्यवधान)... सैकिंड पार्ट का अभी ए भाग चालू है। लिखते गए, लिखते गए, लेकिन कंपनी से नहीं पूछा।

महोदया, एक्चुअली, फरवरी, 2012 में ही अगर इमीडिएटली एक्शन लेते, तो शायद कुछ हो सकता था। वर्ष 2005 में डैक्ल नाम की साउथ अफ्रीका की कंपनी ने कुछ घोटाला किया। जब इस प्रकार की न्यूज़ पेपर्स में आई, तो उन्होंने उसे तीन महीने में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसी सरकार के समय में वर्ष 2005 में उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल दिया गया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले से प्रीसीडेंस नहीं है। इससे पहले सरकार ने ऐसे केसेस के बारे में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। वर्ष 2012 में ही अगर यह डील रोक दी गई होती, तो आगे कई चीजें होती ही नहीं।

महोदया, एक तो जब आपको वर्ष 2012 में ही मालूम हो गया था, तो you should have stopped the supplies of these helicopters. Instead of that the Government did nothing. They did not write to the company and the result was that in December 2012 three helicopters were delivered. एक्चुअली, वर्ष 2012 के दिसम्बर महीने में तीन हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए गए। In December 2012 three helicopters were delivered and were accepted by us. Now, this had further legal complications. पहला एक्शन हुआ 12 फरवरी, 2013 में। एक्शन होने का कारण क्या था, ओरसी, The Chief Executive of M/s Finmeccanica was arrested with a warrant and his house was searched. जब पूरी दुनिया में यह न्यूज़ फ्लैश हो गई, तो Within few hours our Defence Minister picked up all the files, wrote a letter to the CBI and sent it to the CBI immediately. It is an action which was compulsorily forced by an arrest of Chief Executive of Finmeccanica. अगर उन्हें अरैस्ट नहीं किया जाता, तो कुछ नहीं होता। उन्हें अरैस्ट करने के बाद एक दिन के अंदर पूरा केस सी.बी.आई. के पास चला गया और सी.बी.आई. के पास प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होने के बाद, इस केस में 12 मार्च, 2013 को एफ.आई. आर. दर्ज हो गई। On 15th February, 2013, the first notice of stopping the deal and further payment was issued. लेकिन वे वापस उधर ही बैठ गये और आगे कुछ नहीं हुआ। There were notices being exchanged. Finally, चार ...(व्यवधान) अभी पार्ट थ्री न होकर पार्ट टू(ए) है। ...(व्यवधान) On 4th December, 2013, the AWIL, namely, AgustaWestland International Limited issued a notice to the Ministry of Defence that they intend to appoint Justice Srikrishna as their arbitrator and they asked us to appoint our arbitrator within 30 days. The matter was sent to the learned AG. उन्होंने एडवाइज कर दिया कि जो आर्बिट्रेशन क्लॉज इसमें नहीं आता, तब भी उन्होंने जब डिमांड की, It will be in the interest that हम भी आर्बिट्रेटर एप्वाइंट करें। As per the Clause, it has to be done in 30 days. मतलब 3 जनवरी, 2014 से पहले आपको आर्बिट्रेटर एप्वाइंट करना होगा और उसके साथ या उसके पहले प्रिफरेब्ली कांट्रैक्ट टर्मिनेट करना होगा। So, it was a *fait accompli* situation that contract had to be terminated because of legal position on 1st January, 2014. It is again not a pro-active step. It was a forced action. तब तक कुछ नहीं किया था। ...(व्यवधान) उसके बाद termination automatically resulted into ...(व्यवधान) यह जो फोर्स्ड एक्शन हो गया, उसके साथ बैंक गारंटीज भी रिवोक करनी होगी। इसकी भी एडवाइज दी गयी थी, तो वह रिवोक हो गयी। उसमें जो परफोर्मेंस गारंटी 27.81 मिलियन यूरो थी और वारंटी की गारंटी भी 27.81 मिलियन यूरो थी। It is five per cent each and दोनों मिलकर 10 परसेंट थी। जो कांट्रैक्ट परफोर्मेंस फेल्योर के कारण दोनों इन्कैश हो गयी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली में एक इंटीग्रिटी पैक्ट के ऊपर तीन करोड़ रुपये की गारंटी दी गयी थी, वह भी रिवोक हो गयी। लेकिन 250.32 मिलियन यूरो which were given as an advance was not allowed to be paid by Italian Court in Milan.

Now, I do not understand why the bank guarantees were enforceable in Deustche Bank in Milan and why not in India. हमारी एक क्लॉज है, सभी बैंक जो गारंटीज आती हैं, except in case of Russia and one or two cases are there where there are some technical problems, we want these bank guarantees to be encashable and counter-guaranteed by an Indian Bank. यह मिलान में गारंटी थी, लेकिन मिलान में हम जब कोर्ट मे गये और हमने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर दिया, उस समय ...(व्यवधान) मिलान कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि दोनों गारंटी मिलकर 199.62 मिलियन यूरो आपको मिल सकते हैं। इसके ऊपर का अमाउंट 50.7 मिलियन यूरो proportionate to the three helicopters accepted by you will not be paid. यह गलत है कि हमने पूरा एडवांस रिकवर कर दिया। उसमें से 50.7 मिलियन यूरो अभी भी बैंक गारंटी के वहां अटके हुए हैं, जो कोर्ट ने एलाऊ नहीं किये। जो टोटल अमाउंट 255 मिलियन यूरो के समथिंग आया है, उसमें दस परसेंट परफोर्मेंस फेल्योर का है। वह यहां एडवांस के अगेन्स्ट काउंट नहीं कर सकते।

स्पीकर मैडम, यह होने के बाद भी आगे-पीछे फाइल चलती रही। फाइनली 12 मई को, टू(ए) का एंड हो जाता है, जब एक दिन में 12 पेज का नोट लगाकर The Defence Minister finally approved to keep on hold which he could have done in February, 2012. सभी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ...(व्यवधान) On 12th May, 2014, the last day of the polling, eight pages note आफिसर का है।

उसके बाद सबके पास 12 तारीख को पास होकर 12 तारीख को चला गया। मुझे लगता है तब तक एग्जिट पोल भी आ गया था।...(व्यवधान) 2ए खत्म हो गया। लेकिन 2ए में एक और महत्वपूर्ण चीज है, सीबीआई ने 12 मार्च 2013 में केस दर्ज किया था, उसकी कॉपी मांगने के बावजूद दिसंबर तक एन्फोर्समेंट डायरेक्टर को भेजी नहीं गई थी। जब दिसंबर में भेजी गई, उस समय एन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कहां डाल दी, मुझे मालूम नहीं।...(व्यवधान) Do not take it in a wrong way. अपने एनवैलप या ड्रार में कहीं लॉक की होगी, जब तक एनडीए की सरकार न आ जाए, जेटली जी जब तक डिफेंस या फाइनेंस मिनिस्टर न बनें। On 3rd July, 2014 finally the Enforcement Director registered a case under the Money Laundering Act. एन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उसके बाद कन्टीनुअस एक्शन लिया, 11 करोड़ अटैच भी किए, केस कोर्ट में मनी लांड्रिंग का डाला गया। आईडीएस के ... *और कई लोगों के खिलाफ ऑफेंस है। देश में प्रापर्टीज़ जो ... * की हैं, करीब 11 करोड़ की प्रापर्टी अटैच की गई है। उनके खिलाफ रैड कार्नर नोटिस इश्यू किया गया है, उनके खिलाफ इंटरपोल को लैटर रोगेट्री गए हैं।

अभी तक सीबीआई के पास जो डॉक्युमेंट हैं, इटालियन कोर्ट से जो डॉक्युमेंट हैं, 1 लाख 21 हजार और कुछ पेजिस हैं, मतलब 1,22,000 से कम पेपर्स आए हैं। Out of that only 42,000 and odd pages are in English. Along with those English materials around 57 pages of Hindi documents are also there. मतलब यहां से किसी ने चुरा कर दिए होंगे। अभी बाकी के डॉक्युमेंट्स ट्रांसलेट करना ईज़ी नहीं है। ...(व्यवधान) I also face the same problem. They are lucky. I am not. I could not get a proper translator to get them translated from Italian to English. आज तक ऑथेन्टिकेटिड ट्रांसलेशन अभी भी हमारे पास पूरा नहीं है, पार्ट है।...(व्यवधान) ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद हमने सीबीआई और ईडी को कहा है कि इसमें आप बराबर पकड़ो।

इसमें एक चीज ध्यान में आती है कि अगस्टा वैस्टलैंड को आर्डर देने के लिए सब चीजें की गई, इसकी एस्टीमेटिड जेनुअन कॉस्ट से ट्वाइस रेट से ज्यादा में उनको कांट्रेक्ट दिया गया। इसके लिए जो

कुछ रिलैवेंस करना था, वह किया गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्यों शोर कर रहे हैं? किसी का नाम नहीं लिया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर: जब यह चोरी ध्यान में आ गई,...(व्यवधान) उस समय उस कंपनी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की, जब तक it was made almost compulsory by circumstances that you act. Then only action was taken, whereas this Government has already initiated the action. We have already taken action.

मैं गारंटी देता हूं, The investigations which are being held against some people now are very small people. हिंदी में कहावत है - बहती गंगा में हाथ धो लेना।... * हो या ... * हो, इन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया है। बहती गंगा कहां जा रही है, इसे ढूंढने के लिए ही मैंने ईडी को यह बताया। ...(व्यवधान) वह कहां जा रही है, यह उस दिन राज्य सभा में स्पÂष्ट हो गया। मराठी में कहा जाता है, जो अकु खातो, इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अरबी का पता होता है।

श्री मनोहर पर्रिकर: आप ट्रांसलेट कीजिए। मराठी में कहते हैं कि जो अकु की भाजी खाता है उसका ही गला खुजता है। ...(व्यवधान)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अलु को हिंदी में अरबी कहते हैं। अरबी का पता होता है।

â€¦(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : महोदया, किसके गले में खुजली हो रही है, वह समझ गया है। मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है और किसी का नाम नहीं लिया है।...(व्यवधान) मैंने हर एक डेट के साथ, फिगर के साथ जो कहा है, वह आपके रिकार्ड में लिखा हुआ है।...(व्यवधान) I have not referred to them but I can vouch on the figures without even referring to the papers. It is our endeavour that we will take action....(व्यवधान) Put them on hold. Defence Ministry is initiating procedure to blacklist them. ब्लैक लिस्ट करने के बाद अगर मैं ऐसा स्लोगन दे रहा हूं तो इन्हें चिंता करने की क्या जरूरत है।...(व्यवधान) "बहती गंगा में हाथ धोना" इस स्लोगन से इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनमें चिंता क्यों पैदा हुई है, क्योंकि इन्हें पता है कि इस स्लोगन का क्या मतलब है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर(हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, मैं समझता हूं कि देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मैं जिस राज्य से आता हूं, उसे वीरभूमि भी कहा जाता है, जो वीरों की वीरता और बलिदान के लिए पूरे देश में जानी जाती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बैठ जाएं। किसी मुद्दे को रेज़ करने के बाद दोबारा उस पर बोलना होता है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, ऐसा लग रहा है कि प्रोसिक्यूटर के बाद एक्यूज्ड को बुलाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदया, आपके कहने पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ ज्यादा मत कहिए, केवल अपनी बात कहिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, जिस तरह रक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखी है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मैं जिस राज्य से आता हूं वह वीरभूमि के नाम से जानी जाती है और जिसे वीरों की वीरता के लिए और बलिदान के लिए जाना जाता है। चाहे वर्ष 1962, 1965, 1971 का युद्ध हो या कारगिल की लड़ाई हो, हिमाचल के लोगों ने अपनी वीरता दिखाई है। कारगिल की लड़ाई में चार परमवीर चक्र मिले तो उनमें से दो परमवीर चक्र हिमाचल के नौजवानों को मिले। जहां एक ओर वीरों की बलिदान की गाथा है वहीं दूसरी तरफ त्यागी और त्याग की देवी की घूस की गाथा की बात आती है। किसने घूस खाई, कितनी खाई, किस मामले में खाई और यह केवलâ€¦ *तक रुक गई या उसके आगे भी गई।...(व्यवधान)

महोदया, इतना ही नहीं, इसमें जिस तरह से आफिसर, सैन्यकर्मी, राजनीतिज्ञ, मीडिया के लोग शामिल हैं, इसमें केवल पैसा का लालच ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को किस तरह से भ्रष्Âट बनाया गया, यह भी देखने को मिलता है। यह स्पÂष्ट तौर से दिखता है कि पिछली यूपीए की सरकार ने किस तरह से पूरी व्यवस्था को खराब किया। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पता चलता है कि व्यक्तिगत हितों के लिए राÂष्ट्रीय हित को बलिदान किया तो पिछली यूपीए सरकार ने किया है। देश में वीवीआईपीज़ के लिए हैलीकाप्टर्स खरीदे जाने थे, उसमें भ्रÂष्टाचार बढ़चढ़ कर किया और इतना ही नहीं इनका नारा है "खाओ और खाने दो" लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ऐसा हो रहा है कि न खाएंगे और न खाने देंगे और एक ईमानदार व्यक्ति रक्षा मंत्री बनकर यहां आए हैं। यह पहली बार नहीं है कि रक्षा घोटाले में कांग्रेस का या यूपीए सरकार का नाम आया हो।...(व्यवधान) चाहे वÂर्ष 2012 में टाटा ट्रक्स स्कैम की, नेवल वार रूम की, स्कोर्पियन सब-मरीन की बात हो, बोफोर्स कांड हो, उससे पहले सब-मरीन डील की बात हो, जितने भी डिफेन्स स्कैम की बात हो, उनमें कांग्रेस की पिछली सरकारों को देखेंगे तो अपने आप में स्पष्टट रूप से नज़र आएगा कि इनका किस तरह से उसमें हाथ रहा है। किस तरह से इनके अपने लोग थे और केवल कौन लोग थे, जो पूर्व में कांग्रेस के सांसद रहे, मंत्री रहे, उनके परिवार के लोग उन डिफेन्स डील्स के साथ जुड़े रहे या उनकी क्या भूमिका रही है, इसे देश ने आज तक जाना है। पूर्व सांसदों का बेटा हो या एक पूर्व मंत्री हो, जो कोल स्कैम में भी था, उसके परिवार के लोगों को आईडीएस इंफोटेक में किस तरह से पैसा पहुंचा, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आज पूरे देश का मीडिया इसे बता रहा है।

क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ बता पा रही है कि किस तरह से, who are the people behind it? Why was favouritism and protectionism given to Agusta Westland? किस तरह से अनुकूल परिस्थितियाँ बनायी गयीं और संरक्षण दिया गया एक कंपनी को, टेंडर लेने के लिए। यह स्पÂष्ट तौर पर दिखता है, जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर पहले यूरोकॉप्टर- ईसी 225, छः हजार मीटर तक उड़ने के लिए क्वालीफाई करता था, तो 4500 मीटर तक इसलिए तय किया गया ताकि ज्यादा कंपनीज इसमें भाग ले सके, दाम भी कम हो और ज्यादा कंपीटिटिव बिडिंग होगी तो उससे देश को लाभ मिलेगा। लेकिन सारी कंपनीज़ को दर-किनार करके केवल केबिन की हाइट बढ़ाने के चक्कर में, उसकी हाइट 1.8 मीटर करके अपने घूस के दाम भी बढ़ाने का काम किया तो साथ के साथ आप लोग वह भी करते चले गये। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि अभी भी कहीं न कहीं जानकारी का अभाव है।

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, डिफेन्स मिनिस्टर ने स्पीकर को संबोधित करते हुए अपनी सारी बातें कही हैं। इसलिए आप भी उसी को फॉलो कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं रक्षा मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहूंगा कि आखिरकार हाईट 1.8 मीटर क्यों की गयी? क्या दुनिया भर में हाईट 1.8 मीटर ही चलत है या 1.45 मीटर से भी काम चलता है? आपके समय में कौन-से इतने लम्बे वीवीआईपी थे, जिनके लिए हाईट 1.8 मीटर करनी पड़ी, जिसके कारण घूस के दाम बढ़ाने पड़े? मेरा पहला प्रश्न यह है।

जिस प्रकार से, स्पष्ट तौर पर कहा गया कि सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को ब्रॉड बेस्ड रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज उसमें भाग ले सके। Then, why SQRs were made so restrictive which narrowed down the choices to limited range of helicopters? यह कारण है कि ये किस प्रकार से फेवरिटिज्म की तरफ आगे बढ़े, किस तरह से इटली की कंपनी को, पता नहीं इटली के साथ इनका कैसा प्यार है कि वहाँ की कंपनी को एक बहुत बड़ा लाभ दिया गया। ...(व्यवधान) क्यों डिलीट किया जाए, ऐसा क्या है इटली में, जो डिलीट किया जाए।

टैक्नीकल इवैलुएशन का टाइम फ्रेम चार महीने का था, लेकिन उसमें भी दस महीने लगा दिये। जिस तरह से ये लगातार आगे बढ़े हैं और जिस प्रकार से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने आरएफपी डाक्युमेंट खरीदा। यूपीए सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनैशनल लिमिटेड यूके की कंपनी को ठेका दे दिया? बार-बार इटली के कोर्ट्स में ब्रिटिश हाई-कमीशनर की बात आती है कि उनको बातचीत करने के लिए कहा गया, तो क्या इससे स्पÂष्ट तौर पर संकेत नहीं मिलते हैं कि कौन-कौन लोग उसमें जुड़े हुए थे, किस तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, किस तरह से â€¦ *से बात करने के लिए उस समय के इटली के â€¦ *को कहा जाता है। आखिरकार, इसमें कौन-कौन लोग इंवोल्व थे, ये सारी बातें देश के सामने और विस्तार से रखनी चाहिए। यदि वह कंपनी ऑरिजनल इक्वीपमेंट मैनयूफैक्चरर नहीं थी, तो आप लोगों ने उनको क्यों ठेका दिया? आप लोगों की क्या मजबूरी थी कि एडब्ल्यूआईएल, यूके को आपको ठेका देना पड़ा? सारी कंपनीज को दर-किनार करके उस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसने न आरएफपी डाक्युमेंट खरीदा और जो दूसरे देश में कंपनी है, जिसने बैंक गारंटी भी हिन्दुस्तान में देने की बजाए मिलान में जाकर दिया। ऐसी क्या मजबूरी उस समय कांग्रेस पार्टी की रही, उस समय की सरकार की रही कि पैरा 75 के अंतर्गत जितनी छूट देनी थी, सारी छूट देकर उस कंपनी को ठेका दिया गया? क्या इसमें स्पÂष्ट तौर पर भ्रÂष्टाचार की बू नहीं आती? इसी कंपनी के ऊपर ...(व्यवधान) बहुत सारे टीवी चैनल्स ने दिखाया है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने हिन्दुस्तान के सीक्रेट डाक्यूमेंट्स विदेश तक कैसे पहुंचाए? ऐसे कौन लोग पिछली सरकार में थे, जो देश के सुरक्षा दस्तावेज देकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? घूसखोरी एक तरफ है, लेकिन देश के साथ गद्दारी दूसरी ओर है, आप वहां पर भी पीछे नहीं रहे।

यही नहीं, जो फील्ड इवैल्यूएशन टेस्ट है, अगर वह देश के अंदर होना था, उसमें भी कहा गया कि जो "नो कॉस्ट-नो कमिटमेंट" बेसिस पर सारा खर्च उन कंपनीज को करना था तो इनकी सरकार को क्या तकलीफ थी? जो टेस्ट छः से 12 महीने के लिए होना था, उसे कम करके फील्ड इवैल्यूएशन टेस्ट केवल दो महीने क्यों कराया गया? छः से 12 महीने तक के इवैल्यूएशन टेस्ट को केवल दो महीने क्यों कराया गया और इसे विदेश में क्यों कराया गया? आखिरकार यहां की परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होना था। अगर उसे यहां गर्म मौसम में उड़ना था तो वह विदेश की परिस्थितियों में, ठण्डे मौसम में कैसे सही पता चलता? किस उंचाई पर उड़ना था, क्या दो महीने के लिए जो अधिकारी यहां से गए, उन्होंने सही मायने में जाकर उसका टेस्ट कर भी पाए या फिर वे घूमने-फिरने के टूर के लिए गए थे? यहां पर जो तीन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के लिए आए, यहां पर रिपोर्ट में कहा गया कि ये हेलीकॉप्टर उस उंचाई पर उड़ने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह भी स्पष्Âट तौर पर एक प्रश्नचिह्न खड़ा करता है कि किस तरह से उस समय की सरकार ने पैरा 75 का दुरूपयोग किया। ऐसा बार-बार क्यों किया गया, इसका भी मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

इसी तरह से सिंगल वेडर की बात आई, जब मंत्री जी ने कहा कि एस92 सरकोज़ी के जो हेलीकॉप्टर थे, वे भी चार पैरामीटर्स पर फेल हुए और जो एडब्ल्यू101 हेलीकॉप्टर हैं, यह दो पैरामीटर्स पर फेल हुआ तो केवल एक कंपनी को ही पैरा 75 के अंतर्गत रियायत क्यों दी गयी? आखिरकार यह चीज कहीं न कहीं यह संकेत देती है कि आप पहले दिन से चाहते थे कि हम एक ही कंपनी को सारी सुविधाएं दें, किसी न किसी तरह से वह कंपनी क्वालीफाई करे और हम उसका सामान खरीद सकें। मंत्री जी ने बताया कि जनवरी, 2006 में 793 करोड़ रुपये कोट किए गए और सितम्बर, 2008 तक आते-आते उसकी कीमत 4,870 करोड़ रुपये दिखा दी गयी, जो छः गुना ज्यादा है। उस पर इन्होंने एक कांट्रैक्ट निगोशिएशन कमेटी बैठाई। क्या यह कांट्रैक्ट निगोशिएशन कमेटी थी या कमीशन निगोशिएशन कमेटी थी? आप क्या निगोशिएट कर रहे थे? कमीशन? आपको इसका उत्तर देना होगा कि आप उस समय तक क्या करते रहे? क्यों इसे इतना ज्यादा रखा गया? अगर 3966 करोड़ रुपये में अगस्ता वेस्टलैंड ने अपना प्राइस कोट किया तो आप लोगों ने इसे ज्यादा क्यों रखा?

जो लोग इसमें इनवाल्व्ड थे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने उस समय क्या किया? चाहे उस समय के एसपीजी चीफ थे, एनएसए थे या उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी थे, आज वे लोग ऐसे कांस्टीट्यूशनल पदों पर बैठे हैं कि उनको इन लोगों ने इम्यूनिटी तक प्रदान कर दी ताकि उनसे कोई पूछताछ न हो पाए। जब यह जांच चल रही थी, उस समय आपके ही लॉ मिनिस्टर ने यह कहा कि उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, उनसे जांच न की जाए। जब यह बात दुनिया भर में स्पÂष्ट हो गयी कि घूस दी गयी और घूस ली भी गयी तो घूस देने वाले तो जेल में हैं, तो फिर घूस लेने वाले खुले तौर पर क्यों घूम रहे हैं?...(व्यवधान) इसका जवाब आप लोगों को भी देना होगा क्योंकि दो साल आपके पास थे। यह घटना वÂर्ष 2011 में बाहर आ गयी तो उसी समय आपने वह डील कैंसिल क्यों नहीं की? ...(व्यवधान) यह प्रश्न इस पर खड़ा होता है कि इन्होंने दो साल का लम्बा समय क्यों दिया? दो सालों में ये क्या तय कर रहे थे? डिप्लोमैटिक चैनल के माध्यम से तीन-तीन बार इन्होंने सम्पर्क करने का प्रयास किया। वह प्रयास केवल इसलिए किया गया कि समय लिया जाए और उन दो सालों कहीं इटली की कोर्ट से राहत मिल पाए और इनके नेताओं एवं बाकी अधिकारियों पर बात न आ पाए और घूस की बात बाहर न आए। क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया? क्या इसीलिए इन सभी लोगों को इम्यूनिटी दी गयी, आज कोई गवर्नर है, कोई सीएंडजी के पद पर है तो उससे पूछताछ न की जाए। मैं रक्षामंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस जांच को कितनी तेजी के साथ बढ़ाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी भी यह मानती है कि पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है,...(व्यवधान) इनके पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हां, इसमें पैसा लिया गया, इसमें

भ्रÂष्टाचार हुआ।

13.00 hours

अगर भ्रÂष्टाचार हुआ तो हम कहते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस जांच का विरोध क्यों करती है? जब भी इसकी बात की जाती है तो वे इसके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं?...(व्यवधान) यही नहीं जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि नवम्बर, 2012 में यह लक्षण बाहर आ गए थे और इटली में तो पता चल गया था कि इस केस में भ्रÂष्टाचार हुआ है, आपको दो साल तक किसने रोक कर रखा था? इस बात का भी जवाब देना होगा कि क्यों उसमें केवल वÂर्ष 2006 तक की जानकारियां दी गयीं, जबकि पैसा वÂर्ष 2012 तक जाता रहा। इटली के कोर्ट ने भी कहा कि अगर पैसा वÂर्ष 2012 तक दिया गया तो पूर्व की सरकार ने एक-एक साल विलम्ब करके केवल वे लिमिटेड डाक्युमेंट्स क्यों दिए जो पब्लिक डोमेन में पहले से ही अवलेबल थे और बाकी जो डॉक्युमेंट्स थे वे नहीं क्यों नहीं दिए? इस जांच को क्यों रोका गया? सीबीआई नौ महीने तक रोक कर रखती है और ईडी को जांच आगे बढ़ाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं देती है। आगे ईडी भी आठ महीने तक काम नहीं करती है तो क्यों रोका गया? जहां एआईआर-2 में कागज रखे गए, वहां आग क्यों लगती है? बाकी कहीं आग नहीं लगती है, लेकिन जहां ये दस्तावेज रखे गए वहां आग लग जाती है। पूरे सबूत मिटाने का प्रयास किया जाता है। दो साल तक कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन 12 मई को एक दिन में, कृपया मंत्री जी इसको बताएं कि पांच दफ्तरों में यह फाइल कैसे पहुंच जाती है, जबकि दो साल में कोई कदम नहीं उठाया जाता है। ऐसी क्या मजबूरी बन गयी थी? क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे और देश में यह पता चल गया था कि अब तो मोदी जी की सरकार आने वाली है। आज तो आपने औपचारिक तौर पर जेल की गिरफ्तारी दी है, लेकिन जैसे-जैसे इसकी जांच आगे बढ़ेगी, भ्रÂष्ट लोगों को जेल में जाना ही पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, मैं केवल दो बात करके अपना भाÂषण समाप्त कर दूंगा।

महोदया, अभी हाल ही में कांग्रेस के एक वरिÂष्ठ नेता, एक मिडिल मैन â€¦ *दुबई में रहते हैं, वह उनसे मिलने गए। क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में यह है? क्या वह वहां जाकर उनसे मिले थे? उनकी उनसे क्या बातचीत हुई? कितने लम्बे समय तक उनकी बातचीत होती रही? जजमेंट में बार-बार एक नाम आता है...(व्यवधान) चार बार उनका नाम आया।...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : आप नाम बताइए।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मुझे लगता है कि आपको अपने लोगों से नाम पूछ लेना चाहिए...(व्यवधान)

मैंडम, उसमें जो दस्तावेज, जो आज सारे टीवी चैनल्स पर देखने को मिल रहे हैं कि किन-किन लोगों को पैसा दिया गया, कौन-कौन अधिकारी थे, कौन-कौन से पॉलीटिकल लोग थे, कौन-सी फैमिली थी...(व्यवधान) किस की फैमिली का नाम बार-बार आता है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। कौन फैमिली थी, यह जानकारी देश को चाहिए...(व्यवधान) इसके बाद कहा गया कि तीस-तीस मिलियन किसको दिया गया?...(व्यवधान) इस पर भी जानकारी दीजिए।

मैडम, एक नाम चार बार कोर्ट में आया है। ए.पी. भी आया है। एक और बड़ा नाम भी आया है। वह बड़ा है या छोटा है...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : आप नाम लेने से डर क्यों रहे हैं? डर किस बात का है, नाम ले लीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, यह क्या है? यह कोई तरीका है? No, this is not fair. I am sorry to say this.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Anuragh Singh ji, you please conclude now.

...(*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप जब पर्सनली अटैक करते हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई पर्सनली अटैक नहीं कर रहा है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए, आप केस के ऊपर जाइए और केस में क्या है, वह बोलिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लेकिन इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप इसकी बजाय इंडीविजुअल अटैक कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों इंडिविजुअल ले रहे हैं? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने कहा है...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Khargeji, nobody has taken any name. Now, please sit down.

...(*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने नाम लिया है, वह पार्टी का नाम लेते जा रहे हैं...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Anurag Thakur, have you completed now?

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, वह कुछ बोल रहे थे, इसलिए मैं रुक गया।

HON. SPEAKER: I am sorry. Nobody has taken any name.

...(*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष महोदया, जिस व्यक्ति का नाम चार बार उस रिपोर्ट में आया है, अगर उससे इतनी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को है और विशेÂष तौर पर हमारे वरिÂष्ठ नेता खड़गे जी को है तो मैं नहीं चाहता, मैं खड़गे जी का बड़ा सम्मान करता हूं, वह समझ गये किसकी बात हो रही है।

HON. SPEAKER: Mr. Anurag Thakur, please conclude, now.

...(*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं और बगैर किसी का नाम लिये अगर इतनी पीड़ा है, अगर नाम आ जाए तो न जाने कितनी पीड़ा हो जायेगी। इसलिए हम यह चाहते हैं कि अगर हमारे रक्षा मंत्री जी ने किसी के ऊपर तथ्यों के अलावा कोई आरोप नहीं लगाया तो इसकी बधाई मैं रक्षा मंत्री जी को देता हूं। हमने न ही कोई आरोप-प्रत्यारोप करने की बात कही। लेकिन अगर देश की गाढ़ कमाई का पैसा भ्रÂटाचार में, घूस में इटली की कंपनी को तय किया जाता है, उसमें कर दिया जाता है और उस पर आप रोकते हैं कि उसे उठाया भी न जाए तो उसमें स्पष्ट नजर आता है कि उसमें कौन लोग संलिप्त थे। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हर कोई जानता है कि उस समय के डिफैंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अगर यह ईमानदार कहते हैं तो उन ईमानदार व्यक्तियों से गलत काम किसने कराया, उस समय सरकार कौन चलाता था, यह देश में किसी से छिपा नहीं है, यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार बार जिनका नाम लिया गया है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि...

HON. SPEAKER: It is high time now that you conclude.

...(*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, मैंने दो बातें बोलने के कहा था, मेरी पहली बात खत्म नहीं होने दी, खड़गे जी बीच में बार-बार खड़े हो गये। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, please conclude.

...(*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मुझे लगा था कि आज धरना देकर आए हैं, इसलिए थोड़ी शांति होगी, लेकिन आज फिर शोर मचा रहे हैं।

मैडम, क्योंकि जिनका नाम चार बार आया है, कोर्ट में जिन-जिन लोगों के नाम आए, क्या उन लोगों के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, जिन्होंने घूस खाई या इस डील को करवाने के लिए उन्होंने

जितनी मदद अगस्ता वेस्टलैंड की की, उसके ऊपर उचित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए।

इसके अलावा पिलाटस एयरक्राफ्ट, जिसके 75 एयरक्राफ्ट 2012 में खरीदे गये। चार हजार करोड़ रुपये की खरीद 2012 में की गई। इस खरीद में कौन लोग शामिल थे, क्या उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ और किस परिवार का नाम उस भ्रष्टाचार के मामले में आता है? 75 पिलाटस एयरक्राफ्ट खरीदे गये, उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, क्या इसकी जानकारी भी मंत्री जी देंगे?

अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो जानकारी मंत्री जी ने देश के सामने रखी है, उसमें काफी जानकारी देश के सामने आई है कि किस तरह से अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड यू.के. को, जिसके पास आरएफपी डाकूमैन्ट भी नहीं था, उसे आउट ऑफ दि वे जाकर, फेवेरेटिज्म करके, संरक्षण देकर जिस तरह से कांट्रैक्ट दिया गया, यह स्पÂष्ट तौर पर दिखाता है कि उसमें घूस खाई गई और जिन लोगों का नाम इटली की कोर्ट में आया है, हमें केवल वहीं तक सीमित न रहकर इसकी जड़ तक जाकर हर दोÂषी को जेल में पहुंचाना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, माननीय रक्षा मंत्री ने जो बातें कहीं और जो बातें श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहीं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मैं दो साल से पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का सदस्य हूं...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Khargeji, according to the list, I am calling the Members to speak.

...(*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप सिर्फ उधर बोलने का मौका दे रही हैं, इधर मौका नहीं दे रही हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरी समझ में नहीं आता कि 197 के बारे में आप जानते हो।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am going as per the list. यह मेरे द्वारा नहीं बनाई गई।

...(*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे: दो साल से पीएसी में जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You know better.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मुझे हमेशा लगता है कि सीएजी का जो नामकरण है, वह बदल देना चाहिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सारी बातें जानते हो।

â€¦(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : उसका नाम*â€¦* *कर देना चाहिए। इसकी जो किताब है, वह *â€¦* *हो जानी चाहिए और जब भी हम लोगों के सामने वह रिपोर्ट आती है तो सीएजी के बदले हमें लगता है कि वह कांग्रेस आ गई, वह रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि कांग्रेस आ गई।

वह रिपोर्ट पढ़ कर लगता है कि कांग्रेस आ गई। संजय बारू की एक किताब है - The Accidental Prime Minister. यदि इसको हम देखेंगे, जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, वह स्टेटमेंट साफ दिखाता है कि जो संजय बारू साहब ने लिखा, उस वक्त के पी.एम.ओ. में ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट थीं। मुझे आपके माध्यम से तीन-चार बातें रखनी हैं, जो बातें रक्षा मंत्री जी ने कही हैं। एक जो सबसे पहला सवाल कहा कि 1.8 और 1.5, इसमें सदन को जान लेने वाली बात है कि यह बात सत्य है कि सन् 2003 में उस वक्त के पीएमओ के प्रिंसिपल सैक्रेट्री ने, जिनको हमने पद्म विभूÂषण नहीं दिया, पद्म विभूÂषण किसलिए दिया, यह अब पता चलता है कि कांग्रेस ने उनको क्यों पद्म विभूÂषण दिया। उन्होंने कहा कि 1.8 ऑप्शनल होगा। यदि अंग्रेजी की भाÂषा ठीक-ठाक समझ में आती है, महताब साहब यदि बताएंगे ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, पॉइंट ऑफ आर्डर है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत जी आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : 1.8 उन्होंने ऑप्शनल कहा। लेकिन जब सन् 2005 में इनके जो नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि यह मैंडेट्री है। ऑप्शनल और मैंडेट्री का फर्क यदि कांग्रेस समझ जाएगी तो मुझे लगता है कि इसका स्कैम पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि जो नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मैं आपको बताऊं कि कई एक पात्र आए हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जस्टिस श्रीकृष्णा को उन्होंने आर्बिट्रेटर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस कृष्णा आर्बिट्रेटर होंगे। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, पॉइंट ऑफ आर्डर है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : No point of order in rule 197

â€¦(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: उसी जस्टिस श्रीकृष्णा को आंध्र प्रदेश को कैसे डिवाइड करना है, उस कमेटी का अध्यक्ष, बना दिया। FSLRC का अध्यक्ष बना दिया।

माननीय अध्यक्ष : किस बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, रूल बताइए।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Show me the rule.

â€¦(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, रूल नंबर 353 है।

माननीय अध्यक्ष : रूल नंबर 353। बताइए क्या है?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Procedure regarding allegation against any person - no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any member unless the member has given adequate advance notice to the Speaker. इन्होंने सीएजी के बोर में कहा। That should be stock of the record.

HON. SPEAKER: He has not made any allegation.

श्री निशिकान्त दुबे : मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है, इसका पेज नंबर - 9 और 26 पढ़ लीजिए कि पहले हमारे समय में यह ऑप्शनल था और आपने इसको मैंडेट्री किया था। मैंने कोई भी एलिगेशन बिना किताब को देखे नहीं किया। ...(व्यवधान) मैं सांसद हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। ...(व्यवधान) दूसरा सवाल यह है कि आठ हैलिकॉप्टर लेना थे, उनको 12 कर दिया। मेरा दूसरा सवाल यह है, जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है। ...(व्यवधान) इसमें जो सीएजी कह रही है, पेज नंबर - 26 में, वह कह रही है कि उस वक्त के एस.पी.जी. के चेयरमैन के कहने पर ये सारी चीज़ें उन्होंने आठ से 12 हैलिकॉप्टर की हैं। वह जो एस.पी.जी. का जो हैड था, वह मैंडम के साथ बहुत वर्षों से था। सन् 2004 में उसको दो साल के लिए एस.पी.जी. का हैड बनाया गया था। क्या ऐसा कारण था, उस अधिकारी में कि सन् 2004 से ले कर 2011 तक सात साल तक वह एस.पी.जी. का हैड रहा और जब वह रिटायर हो गया तो सन् 2012 में उसको राज्यपाल बना दिया। क्या इससे इससे करप्शन की बू नहीं आती है? ...(व्यवधान) तीसरा सवाल यह है कि जो मंत्री महोदय ने कहा कि सी.बी.आई. को केस जाने के बाद भी सी.बी.आई. ने उसको रजिस्टर नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने किस आधार पर *â€¦* को सी.बी.आई. का डायरेक्टर बनाया? ...(व्यवधान) मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ। ...(व्यवधान) उन्होंने इस केस को रजिस्टर नहीं किया। मैं आपको बड़े ऑथेंटिकेट तरीके से कहता हूँ कि उसकी रिटायरमेंट के बाद ये लोग उसको नैशन ह्युमन राइट्स कमीशन का सदस्य बनाना चाहते थे। नैशनल ह्युमन राइट्स कमीशन की मैंबरशिप में सुÂषमा स्वराज उसकी सदस्य हुआ करती थीं। उनके पास वे गए थे, मैंबर बनने के लिए, जिन्होंने कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को फंसाने का प्रयास किया और जब सुÂषमा स्वराज जी ने कह दिया कि मैं उस कमेटी में आपके काग़ज़ पर लिखने वाली हूँ कि you are the most corrupt person. सुÂषमा स्वराज जी की बात सही साबित हुई कि अभी जो सी.बी.आई. का केस चल रहा है, उसमें करप्शन का 700-800 करोड़ रूपये का केस चल रहा है। उन्होंने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की और जब वह नैशनल ह्युमन राइट्स कमीशन का सदस्य नहीं बना पाए तो उनको उन्होंने यू.पी.एस.सी. का मैंबर बना दिया। क्या इससे करप्शन की बू नहीं आती है?...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिस ई.डी. ने इस केस को रजिस्टर नहीं किया, जिस ई.डी ने इसको चाहा कि पहले फेमा में केस हो जाए और पीएमएलए का केस रजिस्टर के लिए 9 महीने का वक्त लगाया, क्या उस ई.डी. का सम्बन्ध *â€¦*

HON. SPEAKER: No names will go on record.

श्री निशिकान्त दुबे : इन्होंने इस तरह से इस ई.डी. को, सीबीआई को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, सभी को इस केस के लिए जिस तरह से आब्लाइज करने का प्रयास किया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं जाएगा।

â€¦(व्यवधान)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Madam, I have a point of order....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने नाम डिलीट करवा दिए हैं।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, please conclude.

श्री निशिकान्त दुबे : इसके बाद मैं इटेलियन कोर्ट की बात करता हूँ।...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: मैं आपको बताऊँ, यह इटेलियन कोर्ट का जजमेंट है।...(व्यवधान) इटेलियन कोर्ट का जजमेंट पेज नम्बर 193 पर है।...(व्यवधान) उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात कर रहा है।...(व्यवधान) पेज नम्बर 193 में और 204 पर है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए और बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: पेज 163 और 164 में वह प्रधान मंत्री की बात कर रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: पेज नम्बर 9 में वह *â€¦* की बात कर रहा है।...(व्यवधान) आपको अफसोस होता है या नहीं होता है, हमें होता है कि हमारे देश के नागरिक का नाम इटेलियन कोर्ट में जा रहा है।...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूँ कि यह इटेलियन कोर्ट का जजमेंट है।...(व्यवधान) ये यह कह रहा है कि "Break up of bribe of Forces' officers, break up of bribe of bureaucrats or bribes paid to politicians." मैं यह कह रहा हूँ कि यह एयरफोर्स के आदमी का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियन का रिलेशन है या नहीं है।...(व्यवधान) मैं केवल अंत में यह कहना चाहूँगा कि जो केस चल रहा है, एन्फोर्समैंट में जो केस चल रहा है, यह कम्पनियों का एक चार्ट है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यह चार्ट है "Total payment of Euro 70' इसमें *â€¦* को दिया गया, इसके बाद *â€¦* को दिया गया, यह मैं ऑफिशियल कागज आपको कोट कर रहा हूँ। इसके बाद *â€¦* को किया गया।...(व्यवधान) इसके बाद जो वेब कम्पनी बनाई गई, इसके बाद यह ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड, दुबई को दिया गया, जिस दुबई की बात कही कि दुबई में मिलने के लिए गए थे। इसके बाद दूसरा जो है 18.2 मिलियन, मैं इस कागज को ऑफिशियली ऑथेन्टिकेट करूँगा कि ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड, दुबई को दिया गया, इसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड ने ये एसपीए और आईडीएस, जो आपको बता दूँ कि 30 परसेंट एक क्लॉज होता है, ऑफसेट क्लॉज होता है कि यदि आप कहीं से कोई इक्विपमेंट लेंगे तो 30 परसेंट आपको इस देश में बनाना पड़ेगा। उस ऑफसेट क्लॉज का इस आईडीएस में वायलेशन किया गया, सीएजी ने इस बात को लिखा है, उसके लिए कौन सी जाँच है। ये सारी जो कम्पनियाँ हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि गौतम खेतान साहब का जो स्टेटमेंट है। मैं स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूँ।

"*â€¦*admitted that in 2009 on the request of *â€¦* and *â€¦* incorporated M/s Incrust Infotech Solution Private Limited with initial paid-up capital of Rs.1 lakh for taking over the IT Division from IDS, Chandigarh." जिसके माध्यम से यह सारा पेमेंट किया गया है। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि *â€¦* को यदि आपने अरेस्ट कर लिया तो जिन लोगों को यह पेमेंट किया है, ये डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउन्ट हैं, यह बैंक अकाउन्ट किसका है। अकाउन्ट नम्बर 7358440 जो मॉरिशस का अकाउन्ट है, अकाउन्ट नम्बर 310001282 जो स्टेलर मॉरिशस का है। अकाउन्ट नम्बर 73528661 जो मॉरिशस का है, ये सारे अकाउन्ट किसके हैं, किसको यह पेमेंट हुआ है।...(व्यवधान)

इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ग्लोबल सर्विसेज दुबई लिमिटेड लिया गया, *â€¦* ने टू इंडियन सिटिजन के साथ *â€¦* और *â€¦* ये लोग कौन हैं, किसके साथ *â€¦* ने यह

अकाउन्ट बनाया। उसमें से 6,56,872 जो है, वह मीडिया एन्जिम प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इस मीडिया एन्जिम प्राइवेट लिमिटेड का मालिक कौन है? ग्लोबल सर्विसेज को 663 लाख दिया गया। इसके बाद इन्होंने बनाया, â€¦ *और â€¦ *ने अट्रोमैट्रिक्स इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ उसने ट्यूनिशिया के साथ वर्ष 2004 में एग्रीमेंट किया था। इसके बाद जो पेमेंट हुआ है, वह पेमेंट गोल्डन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। वे कौन लोग हैं?

इसके अलावा जो मंत्री महोदय आपने कहा, मेरा यह कहना है कि वर्ष 2011 से केस था और यह केस वÂर्ष 2012 में यदि समाप्त हो जाता तो हो जाता। आपने जो बात की है कि बैन किया गया, मेरे पास जो जानकारी है कि जब यह हेलिकॉप्टर अपने पास आ गया, यह बहुत सीरियस बात है, जब अपने पास यह हेलिकॉप्टर आ गया । प्रधान मंत्री साहब को जब पोखरन जाना था तो कहा गया कि यह हैलीकॉप्टर उड़ पाने की स्थिति में नहीं है जिसकी टैस्टिंग के लिए कहा गया, और 12 फरवरी 2013 को जबकि ओरसी पकड़ा गया इटली में, उसी दिन ...* एक एयरफोर्स का अधिकारी है, वह लिखता है कि जो पैरामीटर्स फैक्टर किए गए थे इस हैलीकॉप्टर के लिए, यह उसके लिए यूज़फुल नहीं है।

मैं यह कह रहा हूँ कि यह कोई इटालियन कोर्ट के कारण नहीं किया गया। जब हमारे अधिकारियों ने यह बात कही कि हैलीकॉप्टर नहीं हो सकता है तो यह उन्होंने टैस्टिंग के लिए लिखा और टैस्टिंग के लिए डेट है 12 फरवरी, 2013 को कहा गया कि एम.आई. 17 की तरह ए.डब्लू. 101 है, यह सही बात है या नहीं हैं? इसके बाद 15 फरवरी, 2013 को इसकी क्लियरैन्स को रोक दिया गया और यह डेट जब आगे बढ़ी तो 15 मार्च, 2013 को यह कहा गया कि अगस्ता वेस्टलैन्ड उड़ पाने की स्थिति में नहीं है। क्या इसके आधार पर एफ.आई.आर. हुआ? दूसरा सवाल यह है कि अगस्ता वेस्टलैन्ड के पहले यह कंपनी वेस्टलैंड थी या नहीं थी? उसने ब्रिटिश एग्रीमैंट के साथ पवनहंस को 22 हैलीकॉप्टर दिये थे या नहीं दिये थे, 21 हैलीकॉप्टर दिये थे या नहीं दिये थे। वे 21 हैलीकॉप्टर बुरी स्थिति में हैं। उनके तीन-चार मेजर एक्सीडैंट हुए या नहीं हुए? जब यह सिचुएशन थी तो किस आधार पर अगस्ता वेस्टलैंड को भारत सरकार ने लेने का प्रयास किया? इसके बाद मेरा यह सवाल है कि ये सारे जो पेमेंट हुए हैं, जो बात आपने खुद कही कि गंगा को आप पकड़ने के लिए जा रहे हैं कि गंगोत्री कहाँ से है, भ्रÂष्टाचार की गंगोत्री कहाँ से है? इन लोगों को ...* या नहीं आती है, हमें ... * आती है। हमारे ... * का नाम आ रहा है, ...* का नाम आया है,...(व्यवधान) बड़े-बड़े लोगों का नाम आया है। देश में नेताओं की स्थिति खराब हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इन सबकी जाँच करिए और इन लोगों को, यदि ...* नहीं है, ...(व्यवधान) इन लोगों ने यदि भ्रष्टाचार नहीं किया है तो कम से कम नेताओं को मुक्ति दीजिए और यह पता चले कि नेता साफ-सुथरे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Jyotiraditya Scindia.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record except what Shri Jyotiraditya Scindia speaks.

...(*Interruptions*)â€¦ *

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने ...* बोला। उसके बाद ... * बोला। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि जल्दी करो ताकि ये नाम नहीं आएँ।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या यह सब ठीक है? क्या आप इसको मानते हैं? उन्होंने बोला। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एलीगेशन नहीं लगाया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उसको एक्सपंज करना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये। आप एक्सपंज करना चाहें तो मैं ज़रूर करूँगी। उन्होंने इतना ही कहा कि ये सब नाम आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जल्दी करो। But it will be expunged. ... *और ये सब एक्सपंज करो।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। सबका बोलना ज़रूरी नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ आप बैठिये। उनको नहीं चाहिए तो एक्सपंज करो, क्या फर्क पड़ना है।

â€¦(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हमने इस सदन में देखा कि भाजपा की जो आदत है, झूठे, निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत, यह अच्छी तरह से आज हमने सदन में देख ली। ...(व्यवधान) जो मायाजाल बुनने की कोशिश दोनों सांसदों ने की है, हमने भी प्रतिज्ञा ली है कि उस मायाजाल को ध्वस्त करके ही हम आपके सामने रखेंगे और आपके द्वारा सदन के सामने और देश के सामने हम तथ्य रखने की कोशिश करेंगे। ...(व्यवधान) असलियत क्या है कि इस डील और इस अनुबंध की शुरूआत हमारी सरकार में नहीं हुई थी, इनकी सरकार में हुई थी जब ये यहाँ बैठे थे। वह 1999 में शुरू हुई थी। ...(व्यवधान) आइ एम नॉट रीडिंग। ...(व्यवधान) सन् 1999 में शुरू हुई थी, अध्यक्ष महोदया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप थोड़ा बैठिये न।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अब थोड़ा सुनने का सब्र रखना होगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बोलिये। यह दोनों तरफ से हो रहा है। अब आप बोलिये, मेरी तरफ ही देखिये।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूं, अध्यक्ष महोदया। ...(व्यवधान) मैं वहां नहीं देख रहा हूं, मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं देखने में बुरी नहीं हूं, देखो।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आप तो मातृशक्ति हैं, अध्यक्ष महोदया।...(व्यवधान) आपका आशीर्वाद इस पूरे सदन को मिलना चाहिए और न्याय भी मिलना चाहिए। हम आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप शुरूआत तो करो।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: जो 1999 में शुरूआत हुई थी, 2003 में जो नियमों की बात इन्होंने की, 6000 मीटर से 4500 मीटर का जो नियम में परिवर्तन लाया गया था, वह यू.पी.ए. सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन एन.डी.ए. सरकार के द्वारा 2003 में लाया गया था और 19 नवम्बर, 2003 को बैठक प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुई थी, बृजेश मिश्रा जी ने सारे आई.एफ.एस.पी.जी. के सभी लोगों को बुलवाया था और उन्होंने कहा था कि यह नियम बदलना चाहिए और उसके बाद 22 दिसम्बर, 2003 को प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी भी लिखी थी कि किस हिम्मत से आपने यह नियम बनाया, इसको आपको बदलना होगा और 4500 मीटर करना होगा। यह नियम बदलने का काम एन.डी.ए. सरकार ने करवाया था। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ, ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, इसकी आदत हमें नहीं है कि हर बात पर आश्चर्य लगाओ, पर प्रश्न जरूर उठते हैं। मुझे आश्चर्य तब हुआ, जब आज के अखबार में हमने पढ़ा कि जो â€¦ * हैं, उन्होंने एक महीने पहले ही अगस्ता वैस्टलैंड को कह दिया था कि एन.डी.ए. सरकार 6000 मीटर से 4500 मीटर का नियम बदलेगी और हमें डील के अन्दर प्रवेश दिया जायेगा। आश्चर्य हमें हुआ और हम रक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, जहां तक कार्रवाई की बात है, हमारा एक साल का कार्यकाल जरूर था और उसका ब्यौरा भी मैं आपको देना चाहता हूं, जब यह मीडिया की रिपोर्ट में आया था, अगले ही दिन भारत के दूतावास रोम को चिट्ठी लिखी गई कि जल्द से जल्दी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल यही नहीं, लेकिन 16 जुलाई, 2012 को नेपल्स के प्रोसीक्यूटर्स ऑफिस को भारत सरकार के द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी। नम्बर दो- 19 अप्रैल, 2012 को ही सी.बी.आई. और ई.डी. को कहा गया था कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक अनुबन्ध को निरस्त करने की बात है, 15 फरवरी, 2013 को भारत सरकार के द्वारा नोटिस अगस्ता वैस्टलैंड को दिया गया था और सारी गतिविधियों को पूर्ण रूप से धारण करने के बाद एक जनवरी, 2014 को कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करके रख दिया। फैक्ट नम्बर चार-12 फरवरी...(व्यवधान) आपको अच्छा मौका मिला है, अनुराग, सुन लो भाई। ...(व्यवधान) 12 फरवरी, 2013 को ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only what Shri Jyotiraditya M. Scindia speaks will go on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: 12 फरवरी, 2013 को इस मामले को यू.पी.ए. सरकार ने सी.बी.आई. के हाथ में सौंपा और 12 दिन के अन्दर यू.पी.ए. सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी सी.बी.आई. ने लॉज की, 25 फरवरी को 12 दिन के अन्दर और जुलाई के महीने में ...(व्यवधान) सुन लो, भइया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, मैं केवल आपकी तरफ ध्यान दे रही हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, सी.बी.आई. ने जुलाई के माह में लैटर रोगेटरी इश्यू किये, मारीशस को, ट्यूनीशिया को, इटली को और आज जब आपकी सरकार को 24 महीने निकल गये, 720 दिन निकल गये, आपने 720 दिन में क्या किया? क्या एक रुपया आपने बरामद किया? क्या एक व्यक्ति को चिन्हित किया, जिसने उसमें भ्रÂष्टाचार किया है? सबसे ज्यादा आश्चर्य तो दो साल की मोहलत में जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने 19 अप्रैल, 2016 को सदन के सामने रखा है, मैं उनको कोट करना चाहता हूं:

> "Letter of request was sent by ED and CBI to Mauritius, Tunisia, Italy, BVI, Singapore, UK वगैरह-वगैरह. The agencies are continuing to pursue responses to the LR from the countries concerned."

यह आठ दिन पहले की बात है तो दो साल में जो हमने एल.आर. भेजे, आज तक आपने उसके जवाब भी इन सारे देशों से नहीं लिए, दो साल के अन्दर यह आपकी गतिविधि रही है?

महोदया, फैक्ट नं - 6। इस सदन में पारदर्शिता की बात की जाती है, जवाबदेही की बात की जाती है और की जानी चाहिए, क्योंकि यह देश इसे जरूर जानना चाहता है। हम कभी इस बात से पीछे नहीं हटे हैं कि उस डील में भ्रÂटाचार हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि भ्रÂष्टाचार हुआ है और उसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। यह हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था।

मार्च, 2013 में पारदर्शिता के आधार पर, जवाबदेही के आधार पर हम सदन में प्रस्ताव लेकर आए थे कि ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी गठित होनी चाहिए ताकि सदन के सारे सदस्य भी उस इंक्वायरी में शामिल हों। जब ये लोग इस तरफ बैठे थे तो उस जे.पी.सी. के प्रस्ताव का विरोध आपने क्यों किया? यह प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। जो लोग आज अपने आपको दूध में धुले हुए कहते हैं, आज उनसे देश की जनता के द्वारा प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपने वÂर्ष 2013 में जे.पी.सी. का विरोध क्यों किया?...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : जे.पी.सी. का विरोध इसलिए किया कि उसमें चेयरमैन आपका होता।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) हम यह प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि जो बैनिंग और ब्लैकलिस्टिंग की बात हुई, तो इसमें पहला कदम यू.पी.ए. सरकार ने उठाई थी। दिनांक 10 फरवरी, 2013 को बैनिंग और ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसकी फाइल नोटिंग है, जिसका संदर्भ रक्षा मंत्री जी ने दिया है, दिनांक 12 मई, 2014 का, कि बैनिंग और ब्लैकलिस्टिंग होनी चाहिए। स्वयं हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस सदन में दिनांक 11 मार्च, 2013 को कहा था कि अगस्तावेस्टलैंड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई नेगोशिएशन भविÂष्य में भी नहीं होगा। यह सदन के पटल पर लिखा हुआ वक्तव्य है।

जहां तक राशि की बात है, तो जब मीडिया में यह उछाला गया, उसके एक दिन बाद ही हमने दिल्ली में केस लॉज किया और डेढ़ साल की मेहनत के बाद 240 करोड़ रुपए भारत सरकार के हमने वापस लिए। रक्षा मंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि इस डील में 45औ राशि दी गयी थी, 1586 करोड़ रुपए दिए गए थे। हमने दिल्ली में बैंक गारंटी इन्कैश करके 240 करोड़ रुपए बरामद किए। वैसा ही केस यू.पी.ए. सरकार ने मिलान के कोर्ट में डाला और डेढ़ साल की मेहनत के बाद 228 मिलियन यूरो, मतलब 1,823 करोड़ रुपए मिलान के कोर्ट से, भारत सरकार के हम वापस लेकर आए। हम लोगों का मतलब, देश का आउटफ्लो 1,586 करोड़ रुपए था और देश का इंफ्लो 240 करोड़ और 1,823 करोड़, 2063 करोड़ रुपए हम देश के वापस लेकर आए हैं।

अध्यक्षा महोदय, केवल वह ही नहीं, 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त के अलावा इनके तीन हेलिकॉप्टर्स, एक-एक हेलिकॉप्टर 300 करोड़ के, तीन हेलिकॉप्टर्स को आज भी ज़ब्त करके भारत सरकार ने देश के अंदर रखा हुआ है। यह हमारा कथन है। आज हमने अपनी बैलेंस शीट आपके सामने रखी है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनकी दो साल की बैलेंस शीट क्या है? दो सालों में आप तो यहां बैठ कर चीख-चीख कर कह रहे हैं। आप देश की जनता को बताएं कि दो सालों में आपने करके क्या दिखाया है? यह देश की जनता जानना चाहती है।

अध्यक्षा महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दो सालों में इन्होंने जो कदम उठाए हैं, वे आश्चर्यजनक कदम हैं। पहला कदम, जिस प्रतिबंध की बात रक्षा मंत्री करते हैं, जो एंटनी जी के निर्देश के अनुसार दिनांक 03 जुलाई, 2014 को जारी हुआ था, उस प्रतिबंध में जो लिखा गया था, उसे मैं कोट करना चाहता हूं।...(व्यवधान) इस प्रतिबंध में लिखा गया था - "â€¦ Put on hold until further orders all procurement and acquisitions cases in the pipeline â€¦ It has also been decided that in cases where the tender process has not yet been started, there shall be no dealing with the above companies till finalization of investigation, and सबसे महत्वपूर्ण - no Request for Information (RFI) and no Request for Proposal (RFP) shall be issued to any of the companies / entities." इसे दिनांक 03 जुलाई को एंटनी जी के निर्देश के आधार पर इस सरकार ने निकाला था। यह मैं कह रहा हूं। पर, वह एंटनी जी के निर्देश के आधार पर था क्योंकि वर्डिंग वही है जो एंटनी जी की फाइल की नोटिंग में है। रक्षा मंत्री जी स्वयं आपको इसका वक्तव्य दे देंगे।

अध्यक्षा महोदय, मैं रक्षा मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कठिनाई हुई, चालीस दिनों के अंदर कौन-सा पहाड़ टूटा कि उस परिपत्र को, जो इसी सरकार ने दिनांक 03 जुलाई, 2014 को जारी किया था, कि चालीस दिनों के अंदर दिनांक 22 अगस्त, 2014 को आपने उन सारे प्रतिबंधों को अगस्तावेस्टलैंड से उठा दिया।

अध्यक्ष महोदया, मैं कोट करना चाहता हूं, प्रतिबंध में डेटेड 22 अगस्त, 2014, अनुच्छेद नंबर 6, लिखा है - "Where a vendor is a sub-contractor, should it matter that one of the sub-contractors is such a company?" उत्तर, आर्डर के अंदर it should not matter that a company under Finmeccanica Group of Companies, जिसका अगस्टा वेस्टलैंड पार्ट है, is a sub-contractor or supplier to a contracting party with the Government of India. इसका क्या मतलब है? आपने बैक डोर की एंट्री दे दी। ...(व्यवधान) कान ऐसे मत पकड़ना, पर कान वैसे पकड़ लेना। बात तो वही हो गई। इसी क्लॉज के अंतर्गत जो 22 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री और इनकी सरकार ने जारी की है, इसी के आधार पर सौ नैवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर दो बिलियन डॉलर की डील में अगस्टा वेस्टलैंड ने आरएफआई अपनी तरफ से डाला है। अगर वह ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो कैसे इन्होंने एलाऊ किया? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं

कि नैक्स्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में आरएफआई का प्रस्ताव अगस्टा वेस्टलैंड की तरफ से कैसे डाला गया? यह प्रेस में भी आया। The Company AgustaWestland has got a lifeline on the grounds of the Ministry of Defence proviso under which AgustaWestland and its parent company Finmeccanica can bid for Defence business, not as prime contractors, but as partners or sub-contractors to principal vendors. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि मैं डॉयरेक्ट एक अनुबंध और कांट्रैक्ट मनोहर पर्रिकर जी से नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक अनुबंध मेरे भाई अनुराग ठाकुर के साथ कर सकता हूं और अनुराग ठाकुर का कांट्रैक्ट इनके साथ हो जाए तो मेरी तो पूरी फ्रीडम हो चुकी है भारत में हर डिफेंस डील में आने के लिए। ...(व्यवधान) यह स्थिति आज सरकार ने उत्पन्न कराई है, जिसका इनको जवाब देना होगा। यह रहा प्रश्न नंबर दो। ...(व्यवधान)

प्रश्न नंबर 3, मैं पूछना चाहता हूं कि 29 अप्रैल, 2016 में पीआईबी की रिलीज निकली थी कि ज्वाइंट वेंचर के लिए जो अगस्टा वेस्टलैंड को स्वीकृति दी गई थी एफआईपीबी की, वह यूपीए सरकार के समय में वÂान 2011 में दी गई थी। मैं मानता हूं कि हमने स्वीकृति दी थी, पर वÂान 2011 में अगस्टा वेस्टलैंड के विरूद्ध कोई भ्रÂष्टाचार का आरोप नहीं था। आज इस सदन में आपके द्वारा मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण था कि 8 अक्टूबर, 2015 को एफआईपीबी की मीटिंग में अगस्टा वेस्टलैंड को एफआईपीबी की स्वीकृति इस सरकार ने क्यों दी, जब वह कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी? इसका उत्तर इस सरकार को देना होगा। रिकार्ड हमारे सामने हैं।

ये बात करते हैं 'मेक इन इंडिया की', 'मेक इन इंडिया' के लिए निमंत्रण इस सरकार ने स्वयं फिन मैकेनिका ग्रुप और अगस्टा वेस्टलैंड को दिया और उनको बोला कि बेंगलुरू एयरो एक्सपो में आप आओ। जिस कंपनी का विरोध ईडी कर रही है, जिस कंपनी का विरोध सीबीआई कर रही है, जिस कंपनी का विरोध भाजपा के एक-एक सांसद कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, हर एक सांसद कर रहा है, उस कंपनी को आप 'मेक इन इंडिया' के एक्सपो में बुला रहे हैं। ...(व्यवधान) कम से कम कुछ मान-सम्मान अपने अध्यक्ष का तो आप रखिए। मैं यह सरकार से कहना चाहता हूं, इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने बोला कि यह बोगस कंपनी है और उस बोगस कंपनी को आप 'मेक इन इंडिया' में बुला रहे हैं। इसका उत्तर इनको देना होगा। जो अभी रक्षा मंत्री जी ने कहा ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज कांक्लूड।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, मुझे पांच मिनट दिए जाएं। इनको नॉर्म्स के बिना एलाऊ किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि रफेल की डील में जो दोनों पार्टीज टाइफून यूरोफाइटर और रफेल क्वालिफाइड थे, कांट्रैक्ट निगोसिएशन एग्रीमेंट जो मेरे भाई अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, उनके बिना रफेल के साथ आपने डील ऑफ दि शेल्फ क्यों की? जो 126 की एयरक्राफ्ट थी, यूपीए सरकार ने 10 बिलियन डॉलर्स में डील के बारे में बात की थी, आपने केवल 36 एयरक्राफ्ट के लिए 9 बिलियन डॉलर्स की डील क्यों करवाई? यह बताना पड़ेगा आपको। ...(व्यवधान) जो आरोप मेरे भाई निशीकान्त दुबे जी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के ऊपर लगाया है, इन्होंने नाम लिया है। मैं पढ़ना चाहता हूं कि â€¦ *की चिट्ठी में क्या लिखा है? â€¦ *की चिट्ठी में लिखा है, "â€¦ *her closest advisers are the people the High Commissioner should target."

मैं हैरान हूं कि क्या इस सरकार का आशय यह है कि देश और विदेश के राजदूत भ्रÂष्टाचार के मामले में हमारे नेताओं के साथ मिलना चाहते हैं, इसका उत्तर इनको देना होगा। इस कागज के पर्चे के अलावा जिसके ऊपर हस्ताक्षर भी नहीं है, नेता का नाम एक भी जगह नहीं है, पूरे विश्व में पूरे किसी कॉंट्रैक्ट में, किसी भी डील में नहीं है।...(व्यवधान) इस एक वाक्य के आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब इनको विनम्रपूर्वक देना होगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कोर्ट ने भी इसी का संदर्भ दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी नेता का नाम लिया जाता है तो इनको तकलीफ होती है। ...(व्यवधान) इसलिए डर भी आ जाता है कि यह शेरनी है।...(व्यवधान) इसलिए आपको शेरनी से डर आता है। ...(व्यवधान) शेरनी को खदेड़ोगे तो उत्तर क्या होगा, आपको मालूम हो जायेगा? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ...* ने स्वयं कहा है कि

> "I have never met one single Gandhi ever in my life, not a phone call, not a letter, not a message, not a mention of me in a memo. I am absolutely sure that no money has been paid to the Gandhis."

जिस जज ने यह जजमेंट निकाला जिसका संदर्भ मेरे भाई लोग उस तरफ से कर रहे हैं, वही जज मेगा का वाक्य है :-

> "We have no evidence against â€¦ *only a mention of her in fax. â€¦ *has only been indicated as someone who will fly in the VVIP helicopter."

फैक्स में हाई कमिश्नर की बात की गई है। ...(व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि जो परिवार की बात की, वह उसी इटालियन कोर्ट के जजमेंट में यह लिखा है कि परिवार केवल ...* के बारे में बात की जा रही है, ...* के बारे में बात नहीं की जा रही है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने दूसरा एविडेंस निकाला है, जो कागज का पीस है, जिसमें हस्ताक्षर भी नहीं हैं और ...* ने कहा है कि यह मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं है। उसमें लिखा गया है, मैं आश्चर्य हूं कि आज देश में यह स्थिति है कि जो लिखा जाए कि हमने इंटरनेट के सोर्स से मालूम किया कि ... *कौन हैं? हमारे देश में बहुत सारे ...* हैं, ... * हैं। ...(व्यवधान) बहुत सारे ... * हैं। वक्तव्य में लिखा गया है कि हमने इंटरनेट के सोर्स से लिया है और आज आप उसके आधार पर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, आपको अफसोस होती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब गवाह ने स्वयं वक्तव्य में कहा है कि

> "It is not clear what he meant by AP."

दूसरे, गवाह ने कहा है कि

> "AP is the symbol from open sources. We could see on the internet that AP stands for Ahmed Patel."

आज उसके आधार पर यह सरकार आरोप लगा रही है। जज मेगा ने कहा है कि

> "This is just a hypothesis, not direct evidence. We have no direct evidence."

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर यह सरकार हर विÂषय पर ... * की स्टेटमेंट लेगी ...(व्यवधान) क्या हमें ... * का स्टेटमेंट लेना चाहिए। उसने कहा है कि इटालियन मैरिन्स के केस में प्रधानमंत्री अपने समकक्ष के साथ मिले थे और कहा था कि गांधी परिवार पर सूचना दो, हम इटालियन मैरिन को रिहा कर देंगे।...(व्यवधान) तो आज इटालियन मैरिन्स रिहा हो गये और उनका जजमेंट भी आ गया। ...(व्यवधान) यह क्या संदर्भ है।

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, he should authenticate the document.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: ... * ने स्वयं कहा है, मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं

> "It was made very clear to me through a number of obtuse channels that if I was willing to denounce a member of the Gandhi family

relating to the so-called VVIP helicopters scandal, all charges and investigation against me would be dropped."

क्या हम इस पर विश्वास करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, रक्षा मंत्री जी ने वÂर्ष 2002 के डिफेन्स प्रोक्योरमेंट, वÂर्ष 2006 के डिफेन्स प्रोक्योरमेंट रूल्स में फील्ड ट्रायल्स की बात की। वÂर्ष 2016 में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि फील्ड ट्रायल्स विदेश में नहीं हो सकता है। सिकॉरस्की हेलिकॉप्टर का फील्ड ट्रायल विदेश में हुआ था। ...(व्यवधान) आज इनको उत्तर देना होगा। ...(व्यवधान)

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक Âषडयंत्र बंद करो,...(व्यवधान) बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करो,...(व्यवधान) सूखा का जवाब दो...(व्यवधान) राजनीति की हत्या करने का जवाब दो।...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए। ...(व्यवधान) हर तीन माह में सदन को रिपोर्ट दिया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि क्या मिटाओगे सत्य के राही को, गिरेबां में देखो झांक कर, अपनी ही नीयत को।...(व्यवधान) धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Manohar Parrikarji, still Prof. Saugata Roy is there to speak. After that, you can reply.

...(*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Hon. Speaker Madam, I am not replying to that. I want authenticated documents of what he has been claiming. It has already been denied on the floor of the House. He is quoting the same documents for which he needs to give authentication to the House. ...(*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, we have had a long discussion on the corruption in the Agusta Westland deal. I must start by complimenting the Minister of Defence that at least in his statement I have not found any untruth. In fact, he has revealed some truths which may not be helpful to the ruling party or palatable to the ruling party because the whole controversy on the Agusta helicopter is why the altitude of the helicopter which the Air Force wanted to be 6,000 metre so that it could go to Siachen, was reduced to 4,500 metre. Now, the Minister has clarified that point. He has said that PMO in December, 2003 observed that the framing of mandatory ORs had effectively led the acquisition into a single vendor situation. It was *inter alia* considered to make the operational altitude of 4,000 as mandatory and higher flying ceiling of 6,000 metres and cabin height of 1.8 metre as desirable operational requirements. So, these basic changes which belied what the Air Force wanted for our VVIP helicopters in the beginning was actually made at the behest of the Prime Minister's office during NDA regime. Thank you for admitting that.

13.49 hours (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

Now, let me briefly state the facts of the case. Much has been spoken. This proposal to buy helicopters was mooted by the Army and Air Force in 1999-2000. Then, all these negotiations went on, altitude was raised, height was fixed. Then India signed a contract with Agusta Westland on 8th February, 2010 for 12 numbers of Agusta Westalnd-101 VVIP helicopters for Rs 3,600 crore. In the beginning of 2012, reports began appearing in Indian newspapers on corruption involved in the deal. Nothing was done by the Government then, but on 12th February, 2013 following the arrest of *â€¦ *â€¦ and *â€¦ *â€¦ on charges of bribing, the CBI registered a case. The deal was put on hold. On 1st January, 2014, the then Government cancelled the chopper deal on grounds that the integrity pact was violated. The Government recovered most of the money paid to the Italian Company. The ED registered a case on 3.7.2014.

Shri Parrikar had asked a question. उनका अरेस्ट होता या नहीं होता तो कुछ नहीं होता, इसका मतलब, he said that the Defence Minister Antony took the step because these people were arrested in Italy. मैं भी आपसे पूछ सकता हूं कि अगर मिलान में अप्रैल, 2008 में कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तो बीजेपी भी इस मुद्दे को नहीं उठाती और आप भी स्टेटमेंट लेकर नहीं आते। आपने पहले क्यों नहीं किया, इस सवाल पर मैं बाद में आऊंगा।

Now, the Milan court has given a 226-page judgement. Before that, it must be remembered that in August, 2013, after the deal was put on hold, the CAG said that the revision of IAF requirement in 2006 led to a single-vendor situation that benefited AgustaWestland. It pointed out the frequent revision of rules for awarding the contract. So, what was suggested by the Prime Minister's Office in 2003 was criticised by the CAG. This was not an act of the UPA Government.

One has to very carefully read the judgement. I have done it. The judgement has two parts: the conclusion where they sentence *â€¦ * for four and a half years in jail, where they sentence*â€¦ * for four years jail; but it also has attached many papers. Those papers include handwritten notes by *â€¦ * Even a handwritten note has been found in *â€¦ * cell in the jail. Most of the quotations made by BJP Members, even of names, are from these handwritten notes which are not a part of the judgement but are just attachments to the main judgement. This is a point which has to be noted.

It is also mentioned in the handwritten note how money was distributed: IAF officers were allotted Euros six million; bureaucracy Euros 8.4 million; a category called 'POL' where Euros three million were earmarked for a person identified as 'AP'; and 'FAM' as Euros 15 to 16. Another handwritten note was recovered from *â€¦ * prison cell. It said, 'Call *â€¦ * in my name. Ask him to call *â€¦ *.'

Here I quote a statement from the then Defence Minister A.K. Antony. On 25th March, 2013, speaking in Kochi, Antony said, 'Yes, corruption has taken place. CBI investigations are at a crucial stage now. We shall not show any mercy to anybody, whoever has taken money, however big he is.' Unfortunately, Shri Antony was not able to follow that up though he was Raksha Mantri for 14 months after that. But he said so and he admitted that corruption was there.

Unfortunately, the judgement in those attachments mentions certain people mentioned by Shri Nishikant Dubey. But I cannot go and one should not go by that. Fortunately, the Raksha Mantri has not mentioned that *â€¦* is a fugitive from law in India. He was away in Dubai. So, even if he has written somebody's name it should not be taken as possible truth. My friends in the ruling Party should take it with a pinch of salt that what *â€¦ *

said is not very important....(*Interruptions*) that is not part of the judgement. प्लीज इतना कानून समझिए कि एक मैन जजमेंट के साथ अनैक्षर रहता है। कुमारी सुष्मिता देव यहां हैं। वे लंदन से बार एट लॉ हैं। वे आपको बताएंगी। ...(व्यवधान)... आप तो पहले सुनो। ...(व्यवधान)...यह 226 पेज का डॉक्युमेंट है। इसमें अगर उनका कोई हैंडरिटिन नोट है, तो कुछ देख सकते हैं। So the matter is very serious because the total bribe amounts to Rs.125 crore in Indian money. So, I have several questions which I will put in a rapid fire way, like they do in quizzes like Kaun Banega Crorepati.

- Whether flying altitude was lowered; if so, when.
- Whether cabin height was increased.
- Whether price escalation was effected; if so, at what rate.
- Whether field trials were conducted.

It is said, and you have said correctly that field trials were not conducted in India.

- Whether court of appeal mentions any note of criticism of *â€¦ **, fugitive from India.

Now, my principal question is to the Defence Minister. Shri Jaitley was the Defence Minister for six months. You came from Goa and became the Defence Minister. You have mentioned that there was corruption.

- What action have you taken in the one-and-a-half years?

You are shouting from the house top against corruption. Tell us specific instances of action taken by the CBI under your Government.

- Apart from the*â€¦ **, who were specifically mentioned in the judgement, have you interrogated anybody? You have sent*â€¦ ** to jail for small bribe. Apart from*â€¦ ** have you interrogated anybody? Is this any investigation?
- You say that Rs.124 crore bribe has been paid. The Government recovered a lot of money but whether the bribe has been recovered. What has the CBI under your Government done in two years? If bribe has been paid, you should have recovered it.

You are trying to name politicians. ...(*Interruptions*) Not you, others. You have not named anybody. I have already complimented you that you have perfected parliamentary practice. I appreciate you for that.

13.59 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

- I want to ask whether you have questioned the DG procurement who is now holding a Constitutional post.
- Whether the Joint Secretary, who was then in bureaucracy and who is now occupying a UN post, has been questioned?
- How many names of political leaders have been mentioned in the court; if so, whose? And, whether you are going to take any action against them? Though I say, hand written notes are no proofs, no judgements etc. They are basically hearsay.

Lastly, I want to refer to paragraph 34 of your Statement.

14.00 hours

Let me refer to paragraph 24 of the Minister's Statement. ...(*Interruptions*) Some times I suspect that in this country the big parties who come to power or go out of power have some sort of understanding. No inquiry took place during Shri Antony's tenure as Defence Minister and no inquiry has taken place in Mr. Parrikar's 18 months tenure as Defence Minister. He has remained totally inactive as far as the inquiry is concerned. This is confirmed in paragraph 24 of the Minister's Statement.

It says: "We must ask ourselves as to why when even though the reports of wrongdoing and unethical conduct by M/s. Finmeccanica in connection with the purchase of these helicopters and initiation of preliminary investigation against the Company in Italy surfaced since February 2012 followed by a report of arrest of M/s. Finmeccanica Chief, the action of putting on hold all procurement/acquisition cases in the pipeline with the entire Finmeccanica Group of Companies and other companies figuring in CBI FIR was approved on file by the then RM only on 12.05.2014 – while the UPA was still there – towards the fag end of the then Government's tenure. It was the present Government that finally issued the order on 03.07.2014."

So, you have only followed in the footsteps of what the earlier Government has done.

Lastly, I want to quote from the *Times of India* report of yesterday. It says that the Italian judge who delivered the verdict in the Agusta Westland chopper deal said on Wednesday that there was no 'direct evidence' linking any Indian politician with the alleged kickbacks to swing the deal in favour of the Anglo-Italian firm. Judge Marco Maria Maiga maintained that his verdict was only against senior officials of the company – he has already put them in jail – and middlemen who had paid bribes to some officials in India and that it was up to Indian sleuths to follow the money trail. Identifying Indian individuals was not in for judgement for Italian courts, he said, adding that his order was based on documents which showed that the family of former IAF Chief S.P. Tyagi received the money till April 2012. Guido Haschke, Carlo Gerosa and middleman Christian Michel have been sentenced by the court. Asked about the cooperation from the Indian Government as he had mentioned 'substantial disinterest on clarification of facts in the case' on behalf of Indian side, he said, "all we had was a copy of the CAG, Request for Proposal and agreement copy".

The Defence Minister is a responsible person. I would request him not to go by insinuations and innuendos floated by people of your own Party. ...(*Interruptions*) Have a proper investigation done. I have asked my questions before. I want to know your reaction to the news report that there is

no proof to link netas with bribes by Italy Judge. What is your reaction to that?

Madam Speaker, I think the truth should come out and honesty should prevail.

HON. SPEAKER: I am sorry. Shri Kirit Somaiya. Prof. Saugata Roy, you cannot speak so long.

PROF. SAUGATA ROY: Shri Anurag Singh Thakur spoke for 25 minutes.

HON. SPEAKER: You also spoke for more than 20 minutes.

PROF. SAUGATA ROY: What can I do? You allowed 15 minutes to Shri Nishikant Dubey and 20 minutes to Shri Jyotiraditya Scindia.

Thank you.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न उठे हैं और जो चर्चा हुई है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है - राम तेरी गंगा मैली हो गई। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जिस आर्मी के प्रति देश का एक-एक नौजवान, एक-एक विद्यार्थी श्रद्धा से देखता है, आर्मी, नेवी का चीफ आज कटघरे में खड़ा है। देश की पीढ़ी को क्या संदेश जा रहा है?

अब बात आती है कि यह कहां से शुरु हुआ, कैसे शुरु हुआ?...(व्यवधान) एक बात सीएजी रिपोर्ट की आई। सीएजी की रिपोर्ट को हर व्यक्ति रैफर कर रहा है। अनेक लोगों ने पढ़ा, यह रिपोर्ट कहती है - In August, 2013, the C&AG Report said that revision of IAF requirement in 2006 restricted the competition. मेरा पहला रक्षा मंत्री जी से है कि जो सिंगल पार्टी वेंडर के लिए जो परिस्थिति निर्मित की गई, उसके बारे में आपने बहुत विस्तार में बताया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पुनः एक बार बताएं कि कैसे not only a single party, but a particular party. ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only Dr. Kirit Somaiya's statement will go on record.

...(*Interruptions*)*â€¦ **

डॉ. किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष जी, मुद्दा क्या है? बिंदु यह है कि भ्रÂष्टाचार हुआ तो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कितना हुआ और फायदा किससे हुआ? ...(व्यवधान) जो चर्चा चल रही है, पत्तो, द मनी ट्रेन।...(व्यवधान) मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। Why should the investigative agencies, the Government and the *Raksha Mantri* sit on them? Who is benefited? Where has the money gone? मैं उसके बारे में कुछ फिगर्स और आंकड़े देना चाहता हूं। मेरे पास एक इटालियन आर्टिकल है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कन्क्लूड कीजिए और प्रश्न पूछिए।

डॉ. किरीट सोमैया: मुझे इटालियन पढ़नी नहीं आती है। मैंने सरकार से कहा कि इटालियन कोर्ट के आफिशियल वर्डिक्ट का ट्रांसलेशन, डाक्यूमेंट्स रपÂष्ट करे। मेरे मित्र सिंधिया जी बहुत अधिकृत तौर से उस फाइल के कोरसपोंडेंट, तिथियां, जजमेंट, जज को रैफर कर रहे थे।

मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि सिंधिया जी ने जो रैफर किया है, क्या यह सरकार की फाइल में है? अगर नहीं है तो सिंधिया जी ये बातें कहां से कैसे लाए? अगर सिंधिया जी के पास यह सब कुछ है तो उनके पास भी जरूर होगा कि ... * का नाम, ... * का नाम आया है? क्या डिफेंस मिनिस्टर बताएंगे कि ... * कौन हैं? ... * कौन हैं? उनकी कंपनियां क्या हैं? कितनी कंपनियों में हैं? कौन सी कंपनियों में हैं? मेरे पास एक सूची है। मैंने यह सूची डिफेंस मिनिस्टर को भेजी है। मैं रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ... * दो कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं? तीसरी कंपनी में डायरेक्टर थे तो तीसरी कंपनी कौन सी थी?

*â€¦ **कितनी कम्पनियों में डायरेक्टर रहे हैं? महोदया, मैं आपके द्वारा अधिकृत तौर पर कहना चाहता हूं कि *â€¦ **का सौ से अधिक कम्पनियों के साथ लेन-देन है या स्वयं की कम्पनियां हैं या डायरेक्टर है या इस प्रकार का पैसा लिया गया।...(व्यवधान) वे कम्पनियां हिंदुस्तान में हैं, वे कम्पनियां टैक्स हैवन में हैं। माननीय सिंधिया जी मोरीशियस का नाम ले रहे थे, पनामा का नाम ले रहे थे उसके लिए कि मनी ट्रेल *â€¦ **को कितना पैसा मिला, किसके द्वारा मिला, कौन-सी कम्पनी में मिला।...(व्यवधान) *â€¦ **हिंदुस्तान में सिर्फ दो या तीन कम्पनी में ही डायरेक्टर बनता है और उसमें से एक कम्पनी उस समय की सत्ताधारी पार्टी के नेता के मित्र परिवार की है, क्या यह कोइंसीडेंस हो सकता है? ...(व्यवधान) वह कम्पनी किसी को दो दुकानें बेचती है। वे दुकानें 50 लाख में बेची जाती हैं। मेरा प्रश्न है कि *â€¦ **की सभी कम्पनियां 50 लाख से साढ़े पांच करोड़ रुपए का प्रोफिट क्या यह इनडायरेक्ट मनी ट्रेल है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, मंत्री जी को बोलने दें।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: महोदया, मेरे पास यह डाक्यूमेंट है। मुझे बताया जाए कि इस प्रकार से कितनी कम्पनीज के साथ *â€¦ **की डीलिंग हुई है।...(व्यवधान) इसमें जो नाम सामने आए हैं, मैं वही बोल रहा हूं। मैं रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की दूसरी डील्स हुई हैं, क्या उनके बारे में भी बताएंगे? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: मैं रक्षा मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ईडी और सीबीआई से आग्रह करेंगे कि *â€¦ **के जिन-जिन कम्पनियों में...(व्यवधान)। आईडीएस एनफोटेक का नाम लिया गया, इसका मालिक कांग्रेस के मित्र परिवार का मंत्री रहा है। क्या यह संयोग की बात है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई उसके और मंत्री महोदय के संबंध थे।...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : अध्यक्ष महोदय, बहुत से सवाल पूछे गए हैं और जो प्रश्न इस विषÂय से संबंधित हैं, उनका मैं सदन में उत्तर दूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सदन को देखने के बाद टीवी पर डिबेट का चित्र याद आ गया है जिसमें आठ-नौ सदस्य बिना एक-दूसरे की बात को सुनते हुए केवल अपनी ही बात कहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप विÂषय से संदर्भित उत्तर दे दीजिए।

श्री मनोहर पर्रिकर : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता हूं।...(व्यवधान) You want me to take those names and I can take. I have the courage but I will go by Parliament practices. They do not want to listen....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए, इन्हें बीच में बोलने की आदत है। आप चेयर को एड्रेस कीजिए। भूरिया जी, आप अब बीच में कोई कमेंट मत कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप किसी के कमेंट का उत्तर मत दीजिए। I have not allowed anybody. So only you have to reply

â€¦(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : अध्यक्ष महोदया, कई सवाल उठाए गए हैं। हाउस के सभा-पटल पर मैं कई तथ्य बताऊँगा। पहला तथ्य है,...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, I am not allowing anybody.

...(*Interruptions*)

श्री मनोहर पर्रिकर : स्पीकर मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो तथ्य रखना है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस वर्ष 1994 में शुरू हुआ है, वर्ष 1999 में नहीं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पहला वाक्य है- Air Headquarters observed in January, 1994....(*Interruptions*) They viewed against the above limitations. They started this process, however, this process got derailed. ...(*Interruptions*)

बाद उसे वर्ष 1999 में वापस रिवाइव किया गया। मैं यह पहला तथ्य बताता हूँ। ...(व्यवधान) I would like to mention another thing as to who did the cabin height to 1.8 metres....(*Interruptions*) I am placing on the Table of the House documents which will prove that it is the UPA Government which did this....(*Interruptions*) This is NSA's minutes of the meeting dated 1st March and the 9th May which in O.R. No. 5 says very clearly that the internal cabin height of, at least, 1.8 metres will be mandatory. This is agreed by all....(*Interruptions*) यह सबने मान लिया है कि पाँचवीं वार नम्बर पर 1.858 मीटर को मैनडेटरी किया, यह 9 मई 2005 का गवर्नमेंट का डाक्युमेंट मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। यह लोग जो असत्य बोल रहे हैं...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Anurag Singh Thakur, please take your seat.

...(*Interruptions*)

श्री मनोहर पर्रिकर :मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो फेक ट्रायल हुई है, ...(व्यवधान) वह बराबर नहीं हुई और जो इन्होंने सवाल उठाये, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री खड़गे जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं कहना चाहता हूँ कि इतना लम्बा-चौड़ा भाÂषण देने के बजाए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एन्क्वायरी होने दीजिए, ...(व्यवधान) अगर वे इसके लिए तैयार हैं, तो हम फेस करने के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : किस बात के लिए एन्क्वायरी?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जो यह वाकया है, जो यह घोटाला है, उसके बारे में एन्क्वायरी कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : मैडम, जो निशिकांत दुबे जी ने बताया और जो यहाँ बताया गया, उसे ध्यान में रखना पड़ेगा।

14.19 hours

(At this stage, Shrimati Sonia Gandhi and some other

hon. Members left the House.)

श्री मनोहर पर्रिकर : निशिकांत दुबे जी ने जो सवाल उठाया कि क्या एयरपोर्ट-टू के ऑफिस में आग लग गयी थी? मैं यहाँ कंफर्म करना चाहता हूँ कि 3 जुलाई, 2014 को श्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आठ दिनों के अंदर एयरपोर्ट-टू के ऑफिस में, जहाँ सब रिकार्ड रखे जाते हैं।...(व्यवधान) एयरपोर्ट ऑफिस-2...(व्यवधान) एयरपोर्ट-2, जहां सब रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जिसमें सब फाइलें रहती हैं, वहां मिस्टीरियसली आग लग गयी थी। ...(व्यवधान) इस मिस्टीरियस आग से सब फाइलें जलकर खाक हो गयीं। मैं जिस कारण से नहीं बोल सकता हूं, अभी मैं इसे भी इनवेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को बोलने वाला हूं, लेकिन जिस वजह से आग लगी थी, वह तय हो जाएगा। जिसके मन में आग लगाने की बात थी, अगर थी तो, मुझे लगता है कि वह अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि जो अधिकारी था, यह मामला सेंसिटिव होने के कारण, उसने अपने पेपर्स अपनी ड्रॉअर में लॉक किए थे। केवल तीन फाइलें बच गयीं और ये तीनों फाइलों एडब्ल्यू101 के संबंध में हैं। मैं निशिकांत जी को करेक्ट करना चाहता हूं, उन्होंने बोला 12 फरवरी, 2013। यह 12 फरवरी नहीं है, वह क्या दिन था, वह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो ओरसी की अरेस्ट हुई, वह 12 फरवरी को हुई, लेकिन यह जो डाक्यूमेंट उन्होंने साइन करके डाला है, यह 11 फरवरी का है। उससे एक दिन पहले का है। आपने गलती से 12 फरवरी कह दिया। उन्होंने लिखा है:

> "Based on the above study considered a basic weight of 13.56 tonnes appended below are the key facts emerging out of the study. â€¦"

जो हम लोगों ने अभ्यास किया, उससे यह फैक्ट आ गया। It further says:

> "Effective pay load capacity at MSL in OGE configuration is nil above 30 degree centigrade. â€¦ "

मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेप्रेचर जाएगा तो यह कुछ भी सामान नहीं उठाएगा। Again it says:

> "With day time temperature usually above 10 degree in most of the plains of North India, pay load capacity in OGE configuration is limited to 300 kg reducing with every degree rise in temperature above 10 degree.
>
> (b) Effective pay load capacity at 3,500 feet, AMSL in OGE configuration is nil above minus five degree.
>
> At Srinagar, 5,450 feet AMSL, effective pay load is nil in OGE configuration at all ranges of temperature. Even in IGE configuration, a reduced pay load is to be accepted. The common VVIP sorties to Nehru Helipad cannot be undertaken. Similar in the case of Gulmarg and Pahalgam, where VVIP sorties have been flown in the past using Mi-17 4 helicopters. â€¦."

उसके आगे वह बोलता है :

"इसलिए इसकी पूरी टेस्टिंग करने की आवश्यकता है।"

अगर फेयर ट्रायल इंडिया में किए गए होते तो पता चलता। Afterwards, a strange message came on 27th of February to stop flying. यह 27 फरवरी को आ गया। हेडक्वार्टर से मैसेज आ गया कि इसको स्टॉप करो और इसकी टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इससे वह सब रुक गया। मुझे मालूम नहीं कि टेस्टिंग करने के बाद वह पास होता या नहीं। I do not go into that. But I have a document to prove that there was a question mark raised. सवाल जरूर उठाए थे और बहुत सीरियस सवाल हैं। अगर इंडिया में फेयर ट्रायल किए गए होते तो उसी समय इस सवाल के जवाब मिल जाते। I am not saying that helicopter is not capable because प्रेजिडेंट को आयरन फिस्ट एक्सरसाइज के लिए पोखरन ले जाना था, इसके लिए यह सवाल आया था। बाद में उन लोगों ने कहा है कि आईजीए कंडीशन में, अर्थात जमीन के नजदीक में, 10-15 फीट ऊंचाई से टेक-आफ करने की केपेबिल्टी होने पर प्रेजिडेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वह वीवीआईपीज के लिए रिस्की है और इसे पहले ही प्रॉपरली चेक करना चाहिए था। अगर हम देश में ही आरएफपी कंडीशन के अंदर पैरा 75 का यूज़ नहीं करते तो मुझे लगता है कई मामलों में पैरा 75 को यूज़ करते समय वीवीआईपी की सुरक्षा की चिन्ता करनी चाहिए थी। वह नहीं की गयी। अलग-अलग सवाल उठाए गए। क्या सरकार एक्शन लेगी? ...(व्यवधान) पिलेटस के बारे में वर्ष 2012 में काफी चर्चा हुई थी, लेकिन जब मैं आया, उस समय 60 या 62 प्लेन्स आलरेडी फ्लाइंग में थे। मुझे यह लगा कि अगर मैं उस समय इसे उठाऊं तो एयरफोर्स के पास पायलट की जो शॉर्टेज 164 पर आई है, वह 1000 पर पहुंच जाती।

So, sometimes, you are under constraint to continue even not in a very healthy atmosphere. मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो इनवेस्टिगेट करूंगा। लेकिन इक्विपमेंट फ्लाई करने से नहीं रोकेंगे और वही हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने उसको ब्लैक लिस्ट किया है, हम लोगों ने नहीं किया है। अभी तक सिर्फ ब्लैकलिस्टिंग हुई है, कार्रवाई अभी शुरू हुई है। यह एडवोकेट के एडवाइस पर है, लेकिन पुट ऑन होल्ड जेटली जी ने 3/07 को किया है। उसके बाद में यह पता चला कि इनके पास कई प्लेटफार्म्स हैं, इसमें से नेवी के शिप्स पर जो गन होती है, उसको फिनमकेनिका की सबसिडयरी बनाती है। क्या हम उस गन का सामान लेना बंद कर दें? मेरा सवाल है कि देश की सुरक्षा पहले है या इन लोगों ने जो पैसा बनाया है वह है? उसके लिए देश की सुरक्षा, राÂष्ट्रपति जी की सुरक्षा आपने डेंजर में डाल दी। ..because you made money, you agreed. May be, which person made it is the question mark. राय जी ने जो कहाâ€¦I am slightly confused. In Rajya Sabha, they were on our side. ...(व्यवधान) लेकिन आपने जो बताया I will correct myself. जो क्वेश्चन इधर रेज़ किया, उसके बारे में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि राÂष्ट्रपति जी की सिक्योरिटी गड्ढे में डाल दी तो क्या अब देश की भी डाल दें। ऐसा मैं नहीं करने वाला हूं। मुझे लगता है कि जेटली जी ने लीगल अडवाइस लेकर, वह तो खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं तो भी उन्होंने प्रोपर तरीके से अडवोकेट जनरल का अडवाइस लेकर, क्योंकि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने सवाल उठाए। हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें फिनमकेनिका का कम्पोनेंट है, पार्ट्स हैं और आइटम्स भी हैं, उनका क्या करेंगे, क्या उनको बंद कर दें? Let the naval ships be without bullets; let the helicopters not fly because parts are being manufactured by Finmeccanica's subsidiary! So, we permitted for contracts, which have been already signed. जो कांट्रेक्ट साइन किए गए हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स सप्लायी करने के लिए परमिशन दे दी क्योंकिâ€¦national security is important.

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने फिनमकेनिका के जितने कांट्रेक्ट्स पाइपलाइन में थे, वह पूरा पुट-ऑन-होल्ड है, एक भी चीज नहीं खरीदी गयी है। So, no one need to worry.

On one thing I was very comfortable and very happy that time and again the then Defence Minister, and now everyone agreed that corruption happened. इसकी खरीद और इसके पैसे का लेन-देन यूपीए के टाइम में हुआ था। स्वाभाविक है कि उस टाइम में हुआ करप्शन हमारे साइड में से किसी ने नहीं किया होगा। उस साइड ने ही किया होगा, अगर किया होगा तो? So, it is basically logical that money has been paid to someone from the other side, not from this side...(*Interruptions*) That part, I think, has been clearly agreed.

Madam Speaker, I would make it very clear that इसके पहले वषÂ◌ार्न 2005 का जो मैंने रेफर किया था â€¦because of Paper reports. The Defence Minister, immediately, based on the Paper report of corruption banned and blacklisted Devel company of South Africa from dealing with the Defence totally.

Are you aware of what happened? पेपर रिपोर्ट के आधार पर तो किया, लेकिन सोचा नहीं। क्योंकि नालंदा में बीएमसी बनाने की जो फेक्ट्री चल रही थी, उसके लिए टेक्नीकल कोलबोरेशन कांट्रेक्ट उनसे किया था। We had paid them the full amount. और सरकार ने बैन डाल दिया कि उनके साथ डील मत करो।...After paying the full amount without thinking that अगर पैसा दिया है तो कम से कम सामान ले लो, उसका टेक्निकल अडवाइस ले लो। वह नहीं ली और ऊपर से पैसा दे दिया, जिसको रिकवर करने की चिंता नहीं की।

While our Government judiciously realized that there are so many products which have components from this company, we permitted only component purchases from national security angle और वह जो बोल रहे हैं कि सब कांट्रैक्टर है, How are you going to find out if Finmeccanica's subsidiary company is supplying one small avionics box to Boeing or Airbus or to someone? How do you know? They might be one of the sub-components. हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि एक पार्ट अगर फिनमैकेनिका से है तो हम नहीं खरीदेंगे। अभी आपको भी मालूम है कि चाइना से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिफैंस के लिए नहीं खरीदते। There is a ban. The WTO permits it on national security reason. Have you put a ban on the Chinese mobile? It is because the ban or the put on hold is only for defence. लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स लेने के लिए नहीं है। If you are going to manufacture a civilian helicopter, it is none of the concern of the Ministry of Defence to stop you from selling your product because if I have not stopped Chinese product from the market which I cannot do legally, how can I stop other's product? तो यह क्या हो रहा है, 'मेक इन इंडिया' में किसने पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन यूपीए वालों ने फिनमैकेनिका को बैन करने के बाद भी परमीशन दी थी। This is dated 22nd February, 2014. मुझे लगता है कि श्री एंटनी डिफैंस मिनिस्टर थे, 2014 में हम नहीं थे। This report indicates that the Ministry of Defence has extended the deadline for the submission of bids in 4.5 billion tender for 56 military transport aircraft in an exceptional move to accommodate the bribery accused, Italian military equipment manufacturing group. अगर आपकी नीयत ठीक थी और आपने उन्हें बैन करने का एक्शन चालू कर दिया था तो How did you permit Alenia C-27J Spartan aircraft which is manufactured by Finmeccanica's Alenia Aermacchi, a Finmeccanica company? Why did you allow them to continue in the process? Luckily for us, this company did not quote and it became single vendor in favour of Airbus. लेकिन आपने इनकी रिक्वैस्ट पर एक्सटेंशन दिया और यह फरवरी, 2014 में दिया। What are they talking about? सब करप्शन के जितने मामले हैं, ब्लैक लिस्ट के जितने मामले आए हैं, उनके जमाने में जितना आर्म्स डील किया है, उसमें ही है। यह सरकार दो वर्ष से है, सीबीआई ने क्या किया, उसका जवाब दे दूंगा। I am proud to say that there is not a single allegation and I had respect for Jyotiraditya Scindia Ji. मैं प्राऊडली बोल रहा हूं कि एलिगेशन अभी तक हमारे ऊपर नहीं आया। लेकिन I am making it very clear that while I thought that Jyotiraditya Scindia Ji is a very good orator, he was totally not true when he said and I am using the word untruth.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : यह अनपार्लियामैन्ट्री वर्ड है।

श्री मनोहर पर्रिकर : असत्य बोल रहे थे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : असत्य बोल रहे थे।

SHRI MANOHAR PARRIKAR: He took total liberties with the truth by saying that राफेल का डील वे कर रहे थे, उसकी कीमत दस बिलियन डालर्स थी। एक तो राफेल का डील हुआ ही नहीं, उनके डिफैंस मिनिस्टर ने उधर लिखकर रखा था, क्योंकि वह डिफैंस मिनिस्टर बहुत डरते थे कि उनकी इमेज ये लोग खराब करेंगे। उन्होंने लिखकर रखा कि एल-1 डिटरमाइन हो गया, आप सीएनसी करो, मतलब प्राइस निगोशिएट करो, फाइनलाइज करो और बाद में मेरे पास वापस लेकर आओ, चैक अप करने के लिए कि यही कंपनी एल-1 है कि नहीं। मैंने जिंदगी में ऐसे कमैन्ट नहीं लिखे। लेकिन उन्होंने खुद का इंश्योरेंस कमैन्ट से निकालकर रखा था। वह करप्शन निगोशिएशन कमेटी, ऐसा डाउट उन्हें भी था। इसके लिए यह सब लिखकर उन्होंने रखा था। उनका अनुभव अगस्टा से यह है, उनको पूरा एक्सपीरिएंस मिला होगा तो यह रफेल डील पर लिखा था। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रफेल डील फाइनलाइज़ किया है, 9 बिलियन डॉलर्स किधर से इनको मिलता है, मुझे मालूम नहीं है। हमने तो पूरा स्टेटमेंट प्रैस में भी दे दिया है। आप प्रेस वाले उसको इतना परफेक्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि कभी-कभी जिसके बारे में भी हो, उसको भी लगता कि हो गया है क्या? हमारी बी.जे.पी. भी उसमें फंस गई। उनके किसी आई.टी. सैल वालों ने लिख दिया कि 8.8 बिलियन डॉलर्स पर यह डील हो गयी है। प्रैस वाले ने मुझे पूछा। मैंने

बोला अभी तक डील नहीं हुआ है। पैसा कम कर-कर के उसमें हम लोग काफी बचाएंगे और दिखा देंगे कि इनके समय जो डील हो रही थी, उस डील से हमारी डील काफी कम कीमत पर होगी। मैं सभी चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ी चीजें जो यहां आ गई, अभी ई.डी. के डायरेक्ट कौन कटोच थे, वह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब सी.बी.आई. के पास एफ.आई.आर. फाइल हो गई 12 मार्च में, उसको ई.डी. में जाने के लिए 8-9 महीने लग गए। After 9 months, in December it reached the ED. From December to June end, the file was kept in a drawer without acting on it. It is on 3rd July, when Arun Jaitley Ji was Finance Minister and Defence Minister that the Enforcement Directorate registered a case under the Money Laundering Act. उसके बाद में एक्शन क्या लिए हैं?

I will tell some actions.

-- 3/7, registration of ECIRDLZO15/2014 under Section 3 of PMLA 2002.

-- 22/9, search at premises of Gautam Khaitan, one of the accused.

--Arrest of Gautam Khaitan.

--PAO No.10/2002-14 related to Gautam Khaitan, his wife Ritu Khaitan and M/s Aeromatrix Info Solutions Private Limited.

-- 15 November, 2014, cognizance taken by court in the criminal complaint against Gautam Khaitan, Ritu Khaitan and others.

--20/12 कोर्ट ने भी मान लिया कि इस केस में मतलब है।

--PAO 4/15, Media Exim Private Limited, the company being run by Christian Michel in the name of R.K. Nanda. इसके खिलाफ केस 31.03.2015 में लगाया।

--Letter of request to competent authorities of Tunisia and Italy on 14.5.2015.

-- PAO 19/2015, attachment related to Tyagi Brothers.

-- 29.9.2015, open ended non-bailable warrant issued in respect of Mr. Christian Michel.

--On 23.10.2015, open ended non-bailable warrant issued in respect of Mr. Gerosa Carlo Valentino Ferdinand, Swiss national, and Mr. Haschke, Italian citizen on 26.10.15....(*Interruptions*)

--Letter of request to UK sent to competent authority on 2.11.2015.

--Letter of request to Singapore and UAE sent to headquarters for onward transmission.

-- Red Corner Notice published against Carlo and Haschke.

-- Red Corner Notice published against Christian Michel on 4.1.2016.

-- Request for extradition of Mr. Christian Michel on 8.1.2016.

ये सब चीजें इटैलियन कोर्ट में हो गई। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Do not answer something like that. No, you need not answer something like that, please.

श्री मनोहर पर्रिकर: हमारी ये सब चीजें इटैलियन कोर्ट का जजमेंट आने के पहले की हैं। सी.बी.आई. ने जो कहा है, वे सब चीज़ें मैं इधर बता नहीं सकता हूँ, because that will actually give...(*Interruptions*). I can tell you this much that CBI is very serious. और छोटे फ्राई, वही तो मैंने बोला, बहती गंगा में हाथ धोने वालों के पीछे अभी इन्क्वायरी चल रही है, लेकिन जो हाथ धो रहे हैं, उनको अंदाजा रहता है कि पानी का टैम्परेचर कितना रहता है, पानी कितनी जोर से बह रहा है तो उनसे हम लोग अंदाजा कर रहे हैं कि पानी किस तरफ बह रहा था, ठंडा था, गरम था, पानी में हिन्दी थी, अंग्रेजी थी, इटालियन थी, जर्मन थी और क्या मामला था। ये सब ट्रैक करने के मामले होते हैं, but I assure you that I will not disappoint you. Though CBI and ED do not come under me, I have already started monitoring the matter. I am also taking interest in the sequence of events personally. ...(*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): How can you monitor the CBI inquiry? It is not under you....(*Interruptions*)

श्री मनोहर पर्रिकर: इन्क्वायरी के बीच में ही सब को छोड़ दें?

HON. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

...(*Interruptions*)

श्री मनोहर पर्रिकर: स्पीकर मैडम, अभी आपने सच बोल दिया। सी.बी.आई. इंडीपेंडेंट है, I am not telling CBI what it should do. I am only finding out whether they are doing something or not. अगर वह नहीं है तो मैं आपको सी.बी.आई. के ऊपर जवाब क्यों दूं। I am not interfering or trying to find out what they are doing. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Minister, please do not answer to anybody's question. Please address the Chair.

...(*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: बैठो न, अगर आपको समझ आ रही है कि क्या कार्रवाई की है।

HON. SPEAKER: Nothing will go in record except the hon. Minister's reply.

...(*Interruptions*)â€¦ *

श्री मनोहर परिकर: आप बैठिये। इनको अगर लगता है, मैं जिसको मोनीटरिंग बोल रहा हूं, वह सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ ऑर्डर का मोनीटरिंग नहीं है तो मेरे शब्द मैं थोड़ा चेंज करता हूं। सी.बी.आई. की प्रोग्रैस मैं मोनेटर कर रहा हूं। I think this will explain to them. I am not going into what CBI is doing but I am checking that they are doing something. मैं सोचता हूं कि इतना तो मुझे करना ही चाहिए। If I do not do that, how will I explain it to Parliament?. ...(*Interruptions*)

स्पीकर मैडम, इससे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एव्रीथिंग एक्सप्लेन हो गया, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कई चीजें यहां बताई गई, उसमें 100 नेवल हैलीकॉप्टर्स के बारे में बात की। हमारी सरकार डिजीटल इंडिया को देखती है तो हम लोगों ने अभी आर.एफ.आई. इण्टरनेट और ओपन इस पर डाल दिया है। जो आदमी चाहे, वह उसके इन्फोर्मेशन डाल सकता है। What is RFI? It is 'Request For Information'. अभी ओपन सोर्स में है और वैबसाइट पर है और किसी को अगर खुद की इन्फोर्मेशन देनी है, चाहे वह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों या â€¦ *हों या अगस्ता वैस्टलैंड हो, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। आर.एफ.आई. में अगर उन लोगों ने डाल दिया तो मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे ध्यान में आ गया, जब इन लोगों ने रेज़ किया। इनका इनके साथ कितना क्लोज़ सम्बन्ध है, वह ध्यान में आ जाता है। I did not know about it that they have loaded their information on RFI. जब ये लोग प्रैस में हवा करने लगे तो मैंने चैक कर लिया। Then, they told me that we cannot stop anyone from what he wants to upload on RFI. Anyone can upload anything. तो इसमें ये भी आ गये हैं। इनका सम्बन्ध â€¦ *के पास है। वह प्रधानमंत्री को क्या लैटर लिखता है, सब डिटेल्स सिंधिया को मालूम है। वे डिटेल्स भी मुझे मालूम नहीं हैं।

हमारे कोंकणी में एक कहावत है, जिसका मतलब है कि जो यात्रा होती है तो गंडेरी जो बेचते हैं, उसके बाजू में रेवड़ी, मतलब तिल और गुड़ का जो होता है, वह बेचते हैं। दोनों गरीब रहते हैं, दोनों का ठौर-ठिकाना नहीं रहता है तो एक का कुछ काम हो गया तो दूसरा उसका पुलिस में विटनैस रहता है। मतलब तो जाहिर ही है, इसके पास कुछ नहीं है तो पुलिस उसको बेल पर रिहा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी बेल स्योरिटी कैसे ले ले, क्योंकि उसका भी कुछ ठौर-ठिकाना नहीं है। इनको कौन विटनैस मिल गया, इनका विटनैस â€¦ * है । ये इधर बोल रहे हैं। हम लोग अगर इटालियन कोर्ट की बात को उठा दें तो वे इम्मीडेटली न्वॉयज़ कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं और वह सुनाई न दे, इसके लिए ये सब कर देते हैं। लेकिन, ये खुद जैसा चाहें, वैसा करते हैं। इन्होंने जज को कोट किया है। मैंने उसे पूरा देखा था। नॉर्मली मैं टेलीविज़न इतना देखता नहीं, लेकिन उस पर्टीक्युलर रिपोर्टर ने मुझे एस.एम.एस. भेज दिया कि देखो जरा। इसलिए मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा - XYZâ€¦.मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। क्यों मैं खाली-पीली बदनाम होऊं? XYZ के खिलाफ हम लोगों के पास एवीडेंस नहीं है। उन्होंने कहा - AP मतलब ......whatever it is. Why do I have to unnecessarily spoil my own reputation by taking the names? पूरी दुनिया को मालूम है कि यह क्या है? सिंगोरा, ये, वह सब मालूम है। Let us not go into that, but the point is that when he said that, he said the next sentence that it is for the Indian investigation authorities to investigate, taking whatever reference I have made in my judgement, and it is for investigation agencies in India to prove guilt of people who are suspected. उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है। जिसने पैसा दिया, उसे जेल में डाल दिया। किसी ने अगर पैसा दिया तो किसी ने तो लिया होगा। मैं नॉर्मली किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन with your permission, you will understand the reference, जो आदमी अभी सी.बी.आई. में ग्रिल हो रहे हैं - *â€¦ *.* वे तो वÂर्ष 2007 में ही रिटायर हो गए। ऑर्डर देने के समय वे नहीं थे। यह ठीक है कि उन्होंने उसे एस.क्यू.आर. ट्रीट करने में मदद कर दी, अन्दर के डॉक्यूमेंट्स को उधर जाने में मदद की होगी। इसके लिए थोड़ा-बहुत प्रसाद उनको मिला होगा। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। पर, ऑर्डर कब गयी? ऑर्डर गयी दिनांक 08 फरवरी 2010 को। उस समय वे नहीं थे। इतने छोटे काम को उन्हें जो मिलना था, वह मिल गया होगा या नहीं मिला होगा, पार्टली मिला होगा। वर्ष 2010 में जिसने इसका ऑर्डर दिया, उसे कितना मिला होगा, वह ढूंढ़ना है। मैं आपको कहता हूं - 250.32 मिलियन यूरो। कई लोगों को लगा कि मैंने राज्य सभा में पढ़ कर दिखाया, वह पहली बार था लेकिन मैं कभी कागज़ नहीं देखता हूं। मेरे मन में पूरे फिगर्स रहते हैं। उस समय 250.32 मिलियन यूरो एडवांस के रूप में पे किए गए थे। उस एडवांस पेमेंट से जो कुछ जिसे मिलना था, वह डिस्ट्रीब्यूट होता होगा।

मेरा स्पष्ट मत है कि इसके लिए उस एडवांस को, जब तक हो सके, तब तक ये लोग वापस विदड्रॉ करने के बारे में सोच नहीं रहे थे, क्योंकि तब तक कुछ मिला नहीं होगा। You can make out the mind. You require a criminal mind to think about a criminal, but you do not have to be a criminal yourself. Why did they immediately not put on hold the full procurement in February, 2012? बेचारे एंटनी के हाथ बांध कर रखे हुए थे। लेकिन, जिस दिन ओर्सी अरेस्ट हो गया, उस दिन उन्होंने यह रियलाइज़ किया कि अभी अगर मैं रूकूंगा तो my sainthood robes would be derobed. इसलिए भाग-भाग कर नोट्स साइन करके, सभी फाइलें सी.बी.आई. के पास उन्होने भिजवा दी। एक दिन में भी नहीं, दो-तीन घंटे में। What I realise from the officers is that he was in panic virtually. He sent it because he wanted to protect his image. I agree up to an extent '*bechara*'. I do not know whether he knew or did not know, but the moment, जब वह कम्पलसरी हो गया, पूरे देश में यह बात आ गयी कि ओर्सी अरेस्ट हो गया, करप्शन चार्ज में अरेस्ट हो गया, रेड हो गयी है, पेपर्स मिले हैं। At that time, Antony did not wait. He immediately went for CBI inquiry. लेकिन सीबीआई को देने के बाद वापस जनवरी, 2014 तक these people again did nothing.

Actually, there are so many irregularities. I am shocked and this is the biggest shock for me. How could you have given an order and accepted tender of a company to whom you have not given the tender? मुझे लगता है कि एक सीवीसी के लिए सफीशिएंट है एक पेपर। They had lost sense of proportion. They thought that they will be permanently in the ruling. The smell of money or the sight of Euro probably was so attractive or intoxicating that यह छोटी-मोटी चीज भूल गए। ...(*Interruptions*)

Actually, they should take consultancy from Michel and some other people. कभी अगर जिंदगी में चांस मिल गया तो कम से कम स्टेपवाइज कैसे खुद के स्टेप्स वाइप ऑफ करने का ...(व्यवधान) हां, लीपापोती कैसे करना है, यह कंसल्टेंसी उनको लेना पड़ेगा।

स्पीकर मैडम, बाकी चीजों में जो उनके एलीगेशंस थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा because if I have to go into allegations, then I will have to take name of the very person for whom he was trying to make those allegations. So, I have decided not to take the names, but I can tell this much as regards this that I will ensure that the CBI and ED do their job. I will not monitor it. वह थोड़ा सा शब्द समझने में गलत गया, लेकिन मैं इतना बोलता हूं कि I will monitor whether they are doing their job or not. I think that it is permitted. हर एक चीज सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो उनके सामने इतने केस हैं ...(व्यवधान) आपने एक बराबर चीज कह दी है Michel Christian is a fugitive. Therefore, they should not treat him as. ...(*Interruptions*) if he is telling gospel truth.

आपको मालूम नहीं है that they can get any document from Michel very fast and within no time. They are lucky, I said because they have support from all these people including Italian translation into English. We will definitely recover bribe - we will recover something like 398 million Euros, which is the damage that we are claiming. This process will start now. In the meantime, I will only say that in October 2014 the lower Italian court had actually said that it is only an income tax theft and not a crime. So, बीच में इसके लिए थोड़ा सा मोमेंटम जो लेटर एलआर होते हैं, उसका इफेक्टिव यह नहीं मिला। With this judgement, the criminal conspiracy is established. We will now get the documents very fast. If you could tell me about good Italian translators because it is very difficult to find them. I am searching because we have so many papers in Italian. ...(*Interruptions*)

Meantime, only one point, which was raised by one of the Members as to whether Westland was banned earlier. I would like to inform him that Pawan Hans Corporation owned by the Government of India was given 21 Westland helicopters in 1985, which were used for oil and natural gas at Bombay High. This was given to them in 1985 under the British grants as the British Government wanted to save this company. Two-three helicopters crashed and then it was realised that this was not very good technically. The question was whether this matter was checked by Air Force when they recommended Agusta Westland (AW) while in 2000 Agusta acquired Westland. I cannot certify that this aspect was looked into. It might not have been visible to them.

I think that I have answered most of the issues, Speaker Madam. I hope Members are satisfied and Members will support the Government in finding

the truth. The truth may lead to very unwanted realism. What we could not do in Bofors, maybe, we will do it in AgustaWestland.

[Placed in Library, See No. LT 4760/16/16]

HON. SPEAKER: Now, if the House agrees, Private Members' Business may be taken up at 4.00 p.m.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: All right.

The House stands adjourned to meet again at 4.00 p.m.

14.55 hours

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.